आयुर्वेदिक चिकित्सा से समाज को स्वास्थ्य लाभ पहुंचा रहे है वैद्य हर्ष सहगल

दिव्य हिमगिरि

हिमालयी राज्यों की पहली साप्ताहिक पत्रिका

नज़र सब पर

15th ANNIVERSARY

वर्ष 15 | अंक 43 | मूल्य 05 रुपये | 15-21 मार्च, 2026

जंग का असर रसोई तक, देश में गैस सिलेंडर की मारामारी

उत्तराखंड में हर घर तक "देवभूमि परिवार" के सहारे विकास की डोर

बजट सत्र में धामी सरकार के बड़े फैसले

दिव्य हिमगिरि

15-21 मार्च, 2026

संपादक
डॉ. कुँवर राज अस्थाना

वरिष्ठ संवाददाता
शंभूनाथ गौतम

संवाददाता
पूनम आर्या

विज्ञापन
सुनील सेमवाल

ग्राफिक डिजायनर
देव भट्ट

संवाददाता
हरिद्वार: डॉ. रजनीश गौतम
पौडी: रत्नमणि भट्ट
कोटद्वार: के.पी. बौंठियाल
रूद्रपुर: हेमचन्द्र बुडलाकोटी
चमोली: मुकेश रावत
रुड़की: श्रीगोपाल नारसन
नैनीताल: शीतल तिवारी
अल्मोड़ा: संजय कुमार अग्रवाल (एड.)
विकासनगर: अजय शर्मा
प्रसार: रमेश सिंह रावत

संपादकीय कार्यालय : 6, म्युनिसिपल रोड, बाला हिसार स्कूल के सामने, डालनवाला देहरादून (उत्तराखंड)
मोबाइल : +91 8433456398, 9410353164
Email: divyahimgiriddn@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक कुँवर बहादुर अस्थाना द्वारा आईशा प्रिंटिंग प्रेस, 292/1, चुक्खूवाला, ओंकार रोड, देहरादून-248001 उत्तराखण्ड से प्रकाशित।
संपादक: कुँवर बहादुर अस्थाना*

*(पीआरबी एक्ट के तहत प्रकाशित सामग्री के लिए उत्तरदायी)

भविष्य के खतरों की चेतावनी

कृत्रिम मेधा पर आधारित चैटजीपीटी को एक सुविधा के तौर पर इसलिए देखा गया था, ताकि जानकारी जुटाने के मामले में लोगों को आसानी हो। मुश्किल और जटिल सवालों का जवाब वह इंसानों की तरह दे। उसने ऐसा किया भी। मगर इस बात पर शायद गौर नहीं किया गया था कि इसे जिस स्वरूप में तैयार किया गया है, उसमें इसका बेजा इस्तेमाल भी आसानी से किया जा सकता है। हालत यह है कि इसके दुरुपयोग की वजह से अब मनुष्य की मेधा ही नहीं,हीं उसका जीवन भी खतरे में आ रहा है। हत्या और आत्महत्या के मामले में 'चैटबाट' के बढ़ते दुरुपयोग को गंभीरता से लेने की जरूरत है। हाल ही में कनाडा के एक स्कूल में हुई गोलीबारी में चैटजीपीटी के दुरुपयोग की खबर सामने आई है। इस घटना में बुरी तरह जख्मी एक छात्रा के माता-पिता ने मुकदमे में आरोप लगाया कि 'चैटबाट' बनाने वाली ओपन एआइ को पहले से मालूम था कि चैटजीपीटी के जरिए हमलावर सामूहिक हत्या की योजना बना रहा था। इस मामले में ओपन एआइ का हैरान करने वाला जवाब है कि उसने हमलावर की गतिविधियों पर विचार किया था, पर पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी। इससे साबित होता है कि चैटजीपीटी का दुरुपयोग किस खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। निराशा की बात है कि इस पर नियंत्रण के लिए कोई नियामक नहीं है। खास क्षमता से दक्ष चैटजीपीटी एक सलाहकार या सहयोगी की तरह काम करता है। यह व्यक्ति की मनोस्थिति के हिसाब से सवालों के जवाब देता है। हत्या या खुदकुशी के मामलों में इसके दुरुपयोग के कई मामले सामने आ चुके हैं। विचित्र बात है कि 'चैटबाट' गलत कदम उठाने को सही ठहरा देता है और अपनी या दूसरों की जान लेने के तरीके बता देता है। मगर इस तरह की गतिविधियों की निगरानी नहीं होती हो, ऐसा संभव नहीं है। कनाडा में हुई गोलीबारी के मामले में ओपनएआइ को हमलावर की गतिविधियों के बारे में पता था। अगर ऐसा है, तो समय रहते इसे रोकने के उपाय क्यों नहीं किए जा सकते हैं? तकनीक के सदुपयोग के साथ दुरुपयोग को रोकने की जवाबदेही तय नहीं की गई, तो आने वाले दिनों में अगर ऐसा है, तो समय रहते इसे रोकने के उपाय क्यों नहीं किए जा सकते हैं? तकनीक के सदुपयोग के साथ दुरुपयोग को रोकने की जवाबदेही तय नहीं की गई, तो आने वाले दिनों में इससे उपजने वाली स्थिति का बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है।

डॉ. कुँवर राज अस्थाना

गैरसैंण की पीड़ा और एक बयान का बोझ

विधान भवन बनाया जाए वेडिंग डेस्टिनेशन

गैरसैंण, मुख्य संवाददाता। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भराड़ीसैंण स्थित विधान भवन परिसर के बेहतर उपयोग पर जोर देते हुए इसे कॉर्पोरेट मीटिंग और वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विस अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण से यह आग्रह किया है।

महाराज ने कहा कि भराड़ीसैंण का विधान भवन परिसर उत्तराखंड की एक महत्वपूर्ण और विशाल परिसंपत्ति है, जिसका विधानसभा सत्र के अतिरिक्त समय में बेहतर उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि सत्र समाप्त होने के बाद इसका उपयोग बड़े कॉर्पोरेट कार्यक्रम, सेमिनार और कार्यशाला के के लिए किया जाए। उन्होंने कहा कि इस परिसर को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी विकसित किया जा सकता है, जिससे अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे परिसर की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

02 महत्वपूर्ण सुझाव देकर अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति पर दिया गया जोर

- पर्यटन मंत्री ने मुख्यमंत्री और विस अध्यक्ष को सुझाव देकर आग्रह किया
- सत्र के बाद कॉर्पोरेट के कार्यक्रम और सेमिनार में उपयोग करने का सुझाव

शीशपाल गुसाईं

उत्तराखंड की राजनीति में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो केवल शब्द नहीं रहते, वे भावना बन जाते हैं, इतिहास बन जाते हैं और कभी-कभी पूरे समाज की आत्मा को छू लेते हैं। "गैरसैंण" भी ऐसा ही एक शब्द है। यह केवल एक स्थान का नाम नहीं है, यह उस आंदोलन की स्मृति है जिसमें पहाड़ के हजारों युवाओं ने अपने सपने और अपने जीवन दांव पर लगाए थे। यह उस उम्मीद का नाम है जो पहाड़ के गांवों में जन्मी थी कि एक दिन राज्य की सत्ता भी उन्हीं पहाड़ों में बैठेगी जहां से राज्य आंदोलन की आवाज उठी थी।

इसीलिए जब गैरसैंण के बारे में कोई हल्का या असावधान बयान सामने आता है तो वह केवल राजनीतिक विवाद नहीं बनता, बल्कि पहाड़ के लोगों के दिल में एक गहरी टीस पैदा करता है। कल मंगलवार को उत्तराखंड के वरिष्ठ मंत्री सतपाल महाराज का वह बयान इसी कारण चर्चा का विषय बन गया जिसमें उन्होंने भराड़ीसैंण स्थित विधानमंडल भवन को भविष्य में वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की संभावना का जिक्र किया।

यह बयान शायद एक सामान्य टिप्पणी के रूप में कहा गया होगा, शायद पर्यटन की संभावनाओं की ओर इशारा करने के लिए कहा गया होगा, लेकिन जिस स्थान का संबंध उत्तराखंड की राजधानी की भावना से जुड़ा हो, वहां इस तरह की टिप्पणी स्वाभाविक रूप से विवाद को जन्म देती है। गैरसैंण केवल एक भवन या परिसर का नाम नहीं है; यह उस सपने का प्रतीक है जिसे राज्य आंदोलन के दौरान हजारों लोगों ने अपने भीतर संजोया था। उत्तराखंड राज्य बनने से पहले लंबे समय तक पहाड़ के लोगों की शिकायत रही कि सत्ता मैदानों में बैठती है और फैसले पहाड़ के जीवन की कठिनाइयों को समझे बिना किए जाते हैं। यही कारण था कि राज्य आंदोलन के दौरान गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग लगातार उठती रही। आंदोलनकारियों का तर्क था कि राज्य का प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्र वहीं होना चाहिए जहां राज्य की भौगोलिक और सामाजिक आत्मा बसती है।

जब वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य बना तो देहरादून को अस्थायी राजधानी बनाया गया। उस समय भी यह उम्मीद जताई गई थी कि भविष्य में राजधानी के प्रश्न पर व्यापक विचार किया जाएगा। लेकिन धीरे-धीरे समय बीतता गया और अस्थायी राजधानी स्थायी व्यवस्था का रूप लेती चली गई।

इसी पृष्ठभूमि में जब भराड़ीसैंण में विधानसभा भवन का निर्माण हुआ तो पहाड़ के लोगों के भीतर एक नई आशा जगी। उन्हें लगा कि शायद अब राज्य की सत्ता धीरे-धीरे पहाड़ की ओर लौटेगी। यही कारण था कि जब तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया तो इसे आंदोलन की भावना को सम्मान देने वाला कदम माना गया। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल भी बना रहा- क्या गैरसैंण वास्तव में प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा, या वह केवल प्रतीकात्मक राजधानी बनकर रह जाएगा?

आज की स्थिति यह है कि भराड़ीसैंण का विधानमंडल परिसर अत्यंत भव्य और आधुनिक है। वहां विधानसभा भवन, विधायक आवास, अधिकारियों के आवास और कई अन्य बुनियादी ढांचे विकसित किए गए हैं। इन परियोजनाओं पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। लेकिन इन सबके बावजूद साल भर में केवल कुछ ही दिनों के लिए वहां विधानसभा सत्र आयोजित होता है।

यही कारण है कि जब वेडिंग डेस्टिनेशन जैसी टिप्पणी सामने आई तो विपक्षी नेताओं ने इसे तुरंत राजनीतिक मुद्दा बना दिया। उनका कहना था कि यदि साल में तीन या चार दिन ही सत्र चलेगा और बाकी समय उस परिसर को विवाह समारोहों के लिए उपयोग किया जाएगा, तो यह उस भावना के साथ न्याय नहीं होगा जिसके कारण गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग उठी थी।

इस पूरे विवाद का एक और महत्वपूर्ण पहलू सतपाल महाराज का राजनीतिक कद भी है। वे उत्तराखंड की राजनीति में केवल एक मंत्री नहीं हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर लंबे अनुभव वाले नेता रहे हैं। जून 1997 से मार्च 1998 के बीच उन्होंने केंद्र सरकार में वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया, उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल व वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम थे। उस दौर में भारत की अर्थव्यवस्था उदारीकरण के महत्वपूर्ण चरण से गुजर रही थी और आर्थिक नीतियों के बड़े फैसले लिए जा रहे थे। ऐसे समय में वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्य करना अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी थी।

जुलाई 1996 से जून 1997 के बीच जब केंद्र में संयुक्त मोर्चा सरकार बनी और सी के जाफर शरीफ रेल मंत्री बने, उस समय सतपाल महाराज रेल राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत थे। उसी दौर में ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के सर्वेक्षण की पहल हुई। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए यह परियोजना लंबे समय से एक सपना रही है और इसे पहाड़ के विकास की जीवनरेखा माना जाता है। वर्षों बाद यह परियोजना

वास्तविक निर्माण के चरण में पहुंची, लेकिन उसके प्रारंभिक विचार और सर्वेक्षण की शुरुआत 1990 के दशक में ही हो गई थी। इसलिए कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इस परियोजना की दिशा तय करने में सतपाल महाराज की भूमिका महत्वपूर्ण रही।

इसी तरह उत्तराखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया में भी उनका नाम लिया जाता है। 1996 के दौर में जब अलग उत्तराखंड राज्य की मांग राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में पहुंच रही थी और उस समय के प्रधानमंत्री एच. डी. देवगौड़ा के नेतृत्व में केंद्र सरकार चल रही थी, तब दिल्ली की राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे को आगे बढ़ाने और विभिन्न नेताओं के बीच संवाद स्थापित करने में सतपाल महाराज की भूमिका को कई लोग महत्वपूर्ण मानते हैं।

यही कारण है कि उनके समर्थक और कुछ राजनीतिक विश्लेषक उन्हें प्रतीकात्मक रूप से "रेल पुरुष" भी कहते हैं। लेकिन राजनीति में उपलब्धियों के साथ-साथ सार्वजनिक शब्दों की जिम्मेदारी भी होती है। कई बार एक छोटा-सा बयान भी बड़ी बहस को जन्म दे देता है। गैरसैंण के संदर्भ में भी यही हुआ। पहाड़ के गांवों में रहने वाले लोग पहले ही इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि राज्य बनने के बावजूद पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन लगातार जारी है। गांव खाली हो रहे हैं, खेत बंजर हो रहे हैं और युवा रोजगार की तलाश में मैदानों या महानगरों की ओर जा रहे हैं।

ऐसे समय में जब गैरसैंण को राजधानी के रूप में विकसित करने की उम्मीद लोगों के मन में अब भी जीवित है, तब वहां के विधानसभा परिसर को विवाह स्थल के रूप में देखने की कल्पना कई लोगों को असहज करती है। यह असहजता केवल राजनीति की उपज नहीं है; यह उस भावनात्मक जुड़ाव का परिणाम है जो पहाड़ के लोग गैरसैंण के साथ महसूस करते हैं।

लेकिन इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा प्रश्न यह भी है कि इतना बड़ा राजनीतिक कद रखने वाला व्यक्ति आखिर ऐसी हल्की टिप्पणी क्यों कर रहा है। सतपाल महाराज कोई साधारण नेता नहीं हैं। वे उस पीढ़ी के नेता हैं जिन्होंने संसद की राजनीति देखी है, केंद्र सरकार में जिम्मेदारियां निभाई हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है।

ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि उनके शब्दों में गंभीरता और दूरदृष्टि दिखाई दे। लेकिन भराड़ीसैंण को वेडिंग डेस्टिनेशन बताने जैसी टिप्पणी कई लोगों को इस कारण भी चौंकाती है कि यह शैली किसी ब्लॉक प्रमुख या स्थानीय नेता की हल्की बयानबाजी जैसी प्रतीत होती है, न कि उस व्यक्ति की जिसने राष्ट्रीय राजनीति में काम किया हो।

यहीं से एक और राजनीतिक प्रश्न जन्म लेता है-क्या सतपाल महाराज जैसे नेता को अनजाने में किसी राजनीतिक खेल का मोहरा बनाया जा रहा है। क्या उन्हें ऐसे विवादों में उलझाकर उनके राजनीतिक कद को सीमित करने की कोशिश की जा रही है।

यह प्रश्न इसलिए भी उठता है क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति में उनका अनुभव और कद असाधारण माना जाता है। एक समय ऐसा भी रहा जब उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व के भीतर अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए कई विधानसभा क्षेत्रों में टिकट वितरण को प्रभावित किया था। कहा जाता है कि उन्होंने सोनिया गांधी के समक्ष अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए आधा दर्जन से अधिक नेताओं के टिकट बदलवा दिए थे।

बाद में वे कांग्रेस से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी में आ गए और भाजपा में आए हुए भी उन्हें एक दशक से अधिक समय हो चुका है। इसके बावजूद यह सवाल अक्सर उठता है कि इतने बड़े अनुभव और राष्ट्रीय पहचान के बावजूद वे राज्य की राजनीति में वह स्थान क्यों नहीं प्राप्त कर पाए जिसकी उनसे अपेक्षा की जाती थी।

कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि इसका एक कारण उनकी सार्वजनिक बयानबाजी की शैली भी रही है। कई बार उनके बयान ऐसे विवादों को जन्म दे देते हैं जिनसे उनका राजनीतिक कद कमजोर होता दिखाई देता है। 2017 में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनी और सतपाल महाराज को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, तब भी कई लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया था। उन्हें लगा था कि केंद्र की राजनीति का अनुभव रखने वाला इतना वरिष्ठ नेता राज्य की राजनीति में सीमित भूमिका में क्यों है।

इस पूरे प्रसंग का एक और पक्ष भी है। आज जब गैरसैंण को लेकर राज्य के भीतर फिर से आंदोलन और राजनीतिक बहस दिखाई दे रही है, तब ऐसे बयान और अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। एक ओर उत्तराखंड क्रांति दल और कांग्रेस पार्टी गैरसैंण के मुद्दे को लेकर आवाज उठा रही हैं, वहीं दूसरी ओर सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी विनोद रतूड़ी जैसे लोग भी गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।

ऐसे समय में यदि भराड़ीसैंण के विधानसभा परिसर को वेडिंग डेस्टिनेशन, मीटिंग हॉल बनाने की बात कही जाए तो स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या इस स्थान की ऐतिहासिक और राजनीतिक गरिमा को समझा जा रहा है या नहीं।

क्या सचमुच उस भवन के प्रांगण में, जहां राज्य की नीतियां तय होती हैं, एक दिन डीजे बजेगा, बैंड बजेगा और जयमाला के मंच सजेंगे? क्या यही वह सपना था जिसके लिए हजारों लोगों ने आंदोलन किया था? क्या यही वह कल्पना थी जिसके लिए राज्य बनने के बाद हजारों करोड़ रुपये खर्च कर भराड़ीसैंण में विधानमंडल परिसर बनाया गया था?

गैरसैंण की पहाड़ियों के सामने एक और ऐतिहासिक स्मृति भी है जो इस बहस को और अधिक भावनात्मक बना देती है। ठीक सामने की पहाड़ियों में कोडियाबगड़ (दूधातोली) का वह क्षेत्र है जहां महान स्वतंत्रता सेनानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की अस्थियों का विसर्जन हुआ था। वही वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जिन्होंने अंग्रेजी शासन के आदेश को ठुकराकर पेशावर में गोली चलाने से इनकार कर दिया था और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर हो गए थे। कहा जाता है कि उन्होंने भी पहाड़ की अस्मिता और सम्मान को ध्यान में रखते हुए कोडियाबगड़ (दूधातोली) को नेहरू जी से राजधानी बनाने की इच्छा व्यक्त की थी। ऐसे में यदि उसी ऐतिहासिक भूमि के सामने लोकतंत्र के मंदिर को विवाह स्थल में बदलने की बात कही जाए तो स्वाभाविक है कि यह पहाड़ की संवेदनाओं को झकझोर देती है।

गैरसैंण केवल एक प्रशासनिक केंद्र नहीं है। यह उत्तराखंड की आत्मा का प्रतीक है। यह उस सपने का प्रतीक है जिसमें पहाड़ के गांवों ने अपने भविष्य को देखा था। इसीलिए पहाड़ के लोगों की दिल की पुकार आज भी वही है-गैरसैंण को केवल एक प्रतीक बनाकर न छोड़ा जाए। उसे उसी सम्मान और महत्व के साथ विकसित किया जाए जिसकी कल्पना उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान की गई थी।

सतपाल महाराज जैसे अनुभवी नेताओं से भी यही अपेक्षा की जाती है कि वे अपने शब्दों के माध्यम से उस भावना को मजबूत करें, कमजोर नहीं। क्योंकि राजनीति में शब्द केवल वाक्य नहीं होते, वे समाज की दिशा तय करने वाले संकेत भी होते हैं। और जब बात गैरसैंण की हो, तो हर शब्द पहाड़ के दिल में गूंजता है।

आयुर्वेदिक चिकित्सा से समाज को स्वास्थ्य लाभ पहुंचा रहे है वैद्य हर्ष सहगल

देहरादून स्थित त्रिलोक आयुर्वेद चिकित्सालय के फाउंडर व सीईओ वैद्य हर्ष सहगल ने विगत 26 वर्षो से आयुर्वेदिक चिकित्सा के माध्यम से अनगिनत लोगों को गंभीर बीमारियों से निजात दिलाई है। एक चिकित्सक के रूप में कई गंभीर बीमारियों के पारंपरिक उपचार से रोकथाम हेतु लगातार कार्य कर रहे है। उत्तराखंड के कई प्रतिष्ठित अवार्डों से सम्मानित वैद्य हर्ष सहगल से उनके इस सफर के बारे में लोकेश राज अस्थाना द्वारा विस्तार से बात की गई। पेश है बातचीत के कुछ अंश।

वैद्य हर्ष सहगल बीएएमएस, एमडी (आयु.)
फाउंडर और सीईओ, त्रिलोक आयुर्वेद
देहरादून, ऋषिकेश

अपनी पारिवारिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बारे में बताईये।

मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से सम्बंध रखता हूँ। मेरा जन्म हरिद्वार में हुआ है लेकिन शुरूआती स्कूली शिक्षा देहरादून में हुई है। मेरे पिताजी पंजाब नेशनल बैंक में विभिन्न राज्यों के प्रमुख रहे है जिस कारण मुझे देश के राज्यों के कई शहरों में रहने का मौका मिला।

चिकित्सा के क्षेत्र में कैसे आना हुआ और इसके पीछे किसकी प्रेरणा रही?

शिक्षा का हमारे परिवार में बहुत प्रभाव रहा है तथा घर के सभी सदस्य वेल एजुकेटेड थे इसिलिए हमसे भी यही अपेक्षा रखी गयी कि हम भी खूब पढे और एक अच्छा कैरियर बनाये। मेरे माता-पिता चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनू और अपेक्षा थी कि इस क्षेत्र में कुछ नया भी करूं। जब यह तय हो गया कि मेडिकल फील्ड में ही जाना है तब मुझे आयुर्वेद से ज्यादा अच्छी संभावना कहीं नजर नहीं आई और बीएएमएस तथा आयुर्वेद से एमडी करने के बाद समाज की सेवा करने का भाव मन में लेकर आयुर्वेद का अपना सफर शुरू किया।

त्रिलोक आयुर्वेद चिकित्सालय के बारे में बताईये।

आयुर्वेद के जरिए मरीजों को ठीक करने के उद्देश्य से देहरादून में वर्ष 2000 में त्रिलोक आयुर्वेद चिकित्सालय की स्थापना की गई। हम हमारे चिकित्सालय में रोगियों का विशुद्ध आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों पर आधारित उपचार करते है। हम हमारी मेडिसिन में इस्तेमाल होने वाली जड़ी-बूटियों का खुद से ही संग्रहण करते है और दवाईयां तैयार करने का हमारा खुद का ही फारमूलेशन है। आज हमारे त्रिलोक आयुर्वेद चिकित्सालय को 26 वर्ष पूर्ण हो चुके है।

आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में विस्तार से बताईयें।

आयुर्वेद का हर मरीज अलग-अलग होता है। मरीज के वेरिएबल्स होते है। उन वेरिएबल्स के आधार पर चिकित्सा को सिंक्रोनाईज किया जाता है। चिकित्सा कभी सटैर्डराईज नहीं हो सकती है। सेम डिजीज के अगर 10 मरीज होंगे तो 10 मरीज के उपर चिकित्सा का फार्मूलेशन अलग अलग हो जायेंगे। ये आयुर्वेदिक चिकित्सा का आधार है।

आपकी प्रमुख उपलब्धियां क्या-क्या रही?

कैरियर की शुरूआत में ही जब मैं 24 वर्ष का था तभी अल्जाइमर (भूलने की बीमारी) रोग में हमें बहुत बडा ब्रेक थ्रू मिला। हमने इसको बहुत ही सफल तरीके से आयुर्वेदिक चिकित्सा से ठीक किया। वहां से फिर ऑटिजम, दूसरी डिजेनरेटिड डिसऑर्डर, मेटॉबालिक डिसआर्डर, ऑटोम्यूनिक डिसआर्डर और कोविड आते-आते हम हार्ट फेलियर को भी ट्रीट करने लगे थे। पिछले लगभग 7 सालों से हम हार्ट ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में कार्य कर रहे है। चूंकि एक आर्गन के हिसाब से इसकी उपलब्धता बहुत सिमित होती है, दूसरे हार्ट ट्रांसप्लांट होने के बाद उसके सक्सेस के चांसेज बहुत लीमिटेड होते है, फिर उम्रभर की दवाईयां और पाबंदियां और ट्रांसप्लांट के बाद कितनी उम्र है वो भी एक इश्यू है। आयुर्वेद के थ्रू हमने उस फारमूलेशन का पूरा खाका डिजाईन किया है कि जहां पर हार्ट टांसप्लाट की जरूरत होती है अगर हमारे पास मरीज सही समय पर आ जाता है तो हम उसे रिवरसल से लेकर कम्पलीट की ओर लेकर जाते है। ऐसे कई केसों को हमने अब तक ठीक करने में सफलता प्राप्त की है। बहुत सारे मरीज ठीक हो चुके है और उसी दिशा में हम अपनी यात्रा को आगे बढा रहे है। इसके अलावा गैस आथारटी ऑफ इण्डिया (गेल) में हमने प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी को लेकर भी एक प्रेजेंटेशन दिया जिसमें हमने बताया कि आयुर्वेदिक मेडिसिन, डाईट, लाईफ स्टाइल चेंज करके किस तरह हम मरीज को पूरी तरह से ठीक करने की दिशा में ले जा सकते है।

आयुर्वेद के द्वारा विभिन्न बीमारियों पर किये जा रहे शोधों के चलते मुझे विभिन्न संस्थाओं द्वारा उत्राखण्ड रत्न, उत्तराखण्ड गौरव, एक्सीलेंस अवार्ड, डॉक्टर ऑफ द ईयर इत्यादि अवार्डों से नवाजा गया है। लेकिन एक चिकित्सक होने के नाते मेरा सबसे बडा अवार्ड तब होता है जब मेरे क्लीनिक से मेरा मरीज ठीक होकर जाता है। तब मुझे सच्चा सुकून प्राप्त होता है।

भविष्य की आपकी क्या-क्या योजनाएं है?

इंसान के जीवन के दो महत्वपूर्ण आर्गन हार्ट और लीवर होते है जिनके कभी-कभी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ जाती है। हालांकि यह इतना आसान नहीं होता। कॉम्प्लीकेटेड होने के साथ-साथ बहुत खर्चीला भी होता है। इस सिचुएशन में मरीज के परिवार के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है विशेषकर जो यंग जनरेशन है उनके लिए। पिछले कुछ वर्षो से हम इन्हीं दो आर्गन के ट्रांसप्लांट को ईजी बनाने की दिशा में कार्य कर रहे है और जन-जन में इस बात को पहुंचा रहे है।

दिव्य हिमगिरी के माध्यम से पाठकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?

पाठकों को यही संदेश देना चाहेंगे कि आयुर्वेद के अनुसार ही अपनी दिनचर्या को बनाकर रखे। जितनी भूख हो उतना खाना खाए, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, व्यायाम करे, सैर करे तथा बुरी आदतों से जितना हो सके उतना बचे और एक स्वस्थ जीवन का आनंद ले। इन तीन चीजों का हमेशा ध्यान रखे

अग्नि- भूख लगने पर ही खाना खाए और खाना पच जाए।

कोष्ठ- सुबह पेट अच्छे से साफ हो जाए।

निंद्रा- रात को नींद अच्छी आए।

याद रखे ''परहेज ईलाज से बेहतर'' है।

बजट सत्र में धामी सरकार के बड़े फैसले

शंभू नाथ गौतम
वरिष्ठ पत्रकार

उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में धामी सरकार ने कई अहम फैसले लिए और वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट सदन से पारित कराया। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आयोजित इस सत्र के दौरान 4 अध्यादेश और 12 महत्वपूर्ण विधेयकों को भी मंजूरी दी गई। हंगामे और विपक्ष के विरोध के बीच चले इस सत्र में विकास, वित्तीय अनुशासन और नई नीतियों को लेकर सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कीं। विभिन्न विभागों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी सदन में विस्तृत चर्चा हुई। यह बजट सत्र 9 मार्च से शुरू हुआ और शुक्रवार देर रात बजट पारित होने के बाद इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।

साल 2027 में होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले धामी सरकार ने अपना आखिरी पूर्ण आम बजट पेश करते हुए विकास की बड़ी रूपरेखा सामने रखी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,11,703.21 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो पिछले साल की तुलना में करीब 10.41 प्रतिशत अधिक है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में पेश किए गए इस बजट को सरकार ने राज्य के समावेशी और तेज विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया। बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार "समावेशी विकास, आत्मनिर्भर नई सोच, तीव्र विकास, उन्नत गांव और शहर, लोक सहभागिता, आर्थिक शक्ति और न्यायपूर्ण व्यवस्था" के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के लिए "केदार परिवेश" और "मानस परिवेश" की अवधारणा के जरिए विकास का नया मॉडल तैयार किया गया है। यह भी पहली बार हुआ जब मुख्यमंत्री धामी ने स्वयं वित्त मंत्री के रूप में सदन में अपनी सरकार का बजट पेश किया। इसके साथ ही पहली बार राज्यपाल के अभिभाषण के तुरंत बाद बजट प्रस्तुत किया गया, जिससे यह सत्र कई मायनों में ऐतिहासिक बन गया। सत्र की शुरुआत उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह के अभिभाषण से हुई। हालांकि सत्र की शुरुआत से ही सदन का माहौल हंगामेदार रहा। विपक्षी विधायकों ने सरकार के खिलाफ तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया और राज्य में भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और आबकारी नीति जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। विरोध के बीच विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी किया। इसके बावजूद सरकार ने बजट को सदन में ध्वनिमत से पारित करा लिया। बजट सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य भी पूरे किए गए। सदन में 4 अध्यादेशों को मंजूरी दी गई, जिनमें उत्तराखंड दुकान और स्थापना (रोजगार विनिमय और सेवा शर्त) संशोधन अध्यादेश 2025, उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश 2025, उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश 2025 और उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2026 शामिल हैं। इसके अलावा 12 महत्वपूर्ण विधेयकों को भी सदन से पारित किया गया। इनमें उत्तराखंड दुकान और स्थापना (संशोधन) विधेयक 2026, उत्तराखंड जन विश्वास (संशोधन) विधेयक 2026, उत्तराखंड माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2026, समान नागरिक संहिता (संशोधन) विधेयक 2026, कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं संशोधन विधेयक, अल्पसंख्यक आयोग संशोधन विधेयक, भाषा संस्थान संशोधन विधेयक, देवभूमि परिवार विधेयक और सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक समेत कई अहम कानून शामिल हैं।

विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी के अनुसार बजट सत्र के दौरान कुल 41 घंटे 10 मिनट तक सदन की कार्यवाही चली। इस दौरान पांच सरकारी संकल्प भी सदन में लाए

गए और कई जनहित के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। विभिन्न दलों के विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े विकास कार्यों और बुनियादी समस्याओं को सदन में प्रमुखता से उठाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में राज्य के वित्तीय प्रबंधन की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और गुड गवर्नेंस के कारण उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। उन्होंने बताया कि नीति आयोग की फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 रिपोर्ट में भी राज्य के वित्तीय प्रबंधन को सराहा गया है और हिमालयी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आयोजित यह बजट सत्र 9 मार्च से शुरू हुआ और शुक्रवार देर रात करीब 12:30 बजे तक चला। इस दौरान धामी सरकार ने एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट पारित कराया, जिसके बाद विधानसभा सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2026-27 का यह बजट आगामी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले धामी सरकार की विकास योजनाओं और प्राथमिकताओं की झलक भी माना जा रहा है। बजट में कई प्रमुख पूंजीगत योजनाओं का भी प्रावधान किया गया है, जिन्हें आने वाले वर्षों में राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

विधानसभा में सीएम धामी ने गिनाई सरकार की बड़ी उपलब्धियां

उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में भाग लेते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियों, नीतियों और आने वाली योजनाओं का विस्तृत उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड आज दृढ़ संकल्प के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और पिछले चार वर्षों में सरकार ने देवभूमि की पहचान और गरिमा को बनाए रखने के लिए कई कठोर लेकिन आवश्यक निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के गठन का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है, जिन्होंने इस राज्य की नींव रखी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र और राज्य की दोहरी इंजन वाली सरकार ने प्रदेश के विकास को नई दिशा और गति देने का कार्य किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट कई मायनों में महत्वपूर्ण है। यह वर्तमान विधानसभा का अंतिम पूर्णकालिक बजट है और आने वाले वर्षों में राज्य के विकास की दिशा तय करने वाला दस्तावेज भी है। इस बार बजट का आकार 1 लाख 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक रखा गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दस प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि यह बजट केवल आय और व्यय का लेखा-जोखा नहीं बल्कि राज्य के सवा करोड़ लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि बजट में दिए गए आंकड़ों से विपक्ष को परेशानी हो सकती है, क्योंकि यह शायद उनके पाठ्यक्रम में नहीं है। उन्होंने कहा कि बजट में मातृशक्ति के सम्मान, युवाओं के उत्थान, किसानों के कल्याण, विज्ञान और नवाचार के विकास, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण तथा पर्यटन के विस्तार को ध्यान में रखते हुए संतुलित विकास का मार्ग तय किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले चार वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद

बजट सत्र के दौरान सदन में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस का धामी सरकार पर हमला

उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भ्रष्टाचार का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया गया। सदन में नियम 58 के तहत हुई चर्चा में कांग्रेस विधायकों ने धामी सरकार को घेरते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार की जड़ें लगातार मजबूत होती जा रही हैं और सरकार का 'जीरो टॉलरेंस' का दावा पूरी तरह विफल साबित हुआ है।

उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार के संरक्षण में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। आर्य ने कहा कि भर्ती घोटाले, योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितताएं और कई अन्य मामलों ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना था कि प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में बिना रिश्वत दिए भवनों के नक्शे पास नहीं होते, जबकि अवैध खनन और खनन डंपरों से पुलिस द्वारा वसूली की शिकायतें भी लगातार सामने आती रही हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विभिन्न योजनाओं में पारदर्शिता की कमी साफ दिखाई देती है। उन्होंने दावा किया कि स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में भी अनियमितताओं का उल्लेख नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में किया गया है। इसके अलावा देहरादून के परेड ग्राउंड के पुनर्विकास कार्यों में भी गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। चर्चा के दौरान उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी ने सरकारी नौकरियों में साक्षात्कार की प्रक्रिया समाप्त कर पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम उठाया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने होम्योपैथिक चिकित्सकों की भर्ती में नियम बदलकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का उदाहरण पेश किया है।

कापड़ी ने शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए कहा कि दिल्ली में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब लगभग 60 रुपये में मिलती है, जबकि उत्तराखंड में वही किताब करीब 100 रुपये में बेची जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भर्ती घोटालों ने प्रदेश में रोजगार के नाम पर सौदेबाजी की तस्वीर को उजागर कर दिया है।

उन्होंने यह भी कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 67 हजार से अधिक सरकारी बसें बिना फिटनेस के चल रही हैं। यह स्थिति गंभीर चिंता का विषय है और इससे यह सवाल खड़ा होता है कि फिटनेस प्रमाणन की प्रक्रिया में आखिर क्या गड़बड़ी हो रही है। वहीं बजट सत्र के दौरान विधानसभा परिसर में भी कांग्रेस विधायकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा परिसर में कांग्रेस विधायक रसोई गैस की आपूर्ति में कमी को लेकर विरोध जताते हुए विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठ गए और धरना दिया। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि प्रदेश में गैस सिलेंडरों की आपूर्ति प्रभावित हो रही है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से इस समस्या का तत्काल समाधान करने और व्यवस्था को सुचारु बनाने की मांग की।

में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और प्रति व्यक्ति आय में लगभग 41 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही राज्य का बजट आकार भी करीब 60 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 1 लाख 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। निवेश, उद्योग और पर्यटन के क्षेत्र में भी राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 30 से अधिक नई नीतियां लागू की हैं। इन नीतियों के परिणामस्वरूप प्रदेश में 20 हजार से अधिक नए उद्योग स्थापित हुए हैं। वहीं नवाचार आधारित उद्यमों की संख्या 700 से बढ़कर लगभग 1750 हो गई है। पर्यटन, होटल और होमस्टे क्षेत्र में भी तेजी से विस्तार हुआ है, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में सख्त नकलरोधी कानून लागू कर नकल माफिया पर कड़ा प्रहार किया है। इस कानून के लागू होने के बाद भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है और अब तक लगभग 30 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार के मामलों में भारतीय प्रशासनिक सेवा और प्रांतीय सिविल सेवा के अधिकारियों सहित 200 से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कई ऐतिहासिक और दूरगामी निर्णय भी लिए हैं। उन्होंने बताया कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन चुका है। इस कानून से महिलाओं को समान अधिकार मिले हैं और समाज में समानता तथा न्याय की भावना मजबूत हुई है। साथ ही राज्य की सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने के लिए सख्त भू-कानून और धर्मांतरण विरोधी कानून जैसे कदम भी उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से प्रदेश में लगभग दो लाख करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विभिन्न विकास परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, चारधाम सर्वकालिक सड़क परियोजना और कई रोपवे परियोजनाएं राज्य के विकास को नई गति देंगी और संपर्क व्यवस्था को मजबूत बनाएंगी। किसानों के हितों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसानों को तीन लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि कृषि उपकरणों पर 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए भी अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं और प्रदेश की लगभग 1 लाख 70 हजार महिलाएं 'लखपति दीदी' बन चुकी हैं। वहीं युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार लगातार नई पहल कर रही है।

उत्तराखंड में हर घर तक "देवभूमि परिवार" के सहारे विकास की डोर

देवभूमि उत्तराखंड में योजनाओं के प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में चल रहे बजट सत्र के दौरान विधानसभा में "देवभूमि परिवार विधेयक-2026" पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य के हर परिवार का एकीकृत और सत्यापित डेटाबेस तैयार करना है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सही पात्र तक पारदर्शी तरीके से पहुंच सके। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की वरिष्ठ महिला को परिवार का मुखिया मानकर पंजीकृत किया जाएगा, जिससे महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा।

देवभूमि उत्तराखंड में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और हर पात्र व्यक्ति तक सरकारी लाभ पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में चल रहे बजट सत्र के दौरान विधानसभा में "देवभूमि परिवार विधेयक-2026" पेश किया। सरकार का मानना है कि यह विधेयक राज्य में कल्याणकारी योजनाओं के संचालन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दरअसल, लंबे समय से यह महसूस किया जा रहा था कि विभिन्न विभागों के पास लाभार्थियों का अलग-अलग

डाटा होने के कारण कई बार योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर नहीं पहुंच पाता। कई मामलों में एक ही व्यक्ति का नाम कई योजनाओं में अलग-अलग तरीके से दर्ज हो जाता है, तो कहीं जरूरतमंद लोग लाभ से वंचित रह जाते हैं। इन्हीं चुनौतियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने "देवभूमि परिवार" नाम से एक एकीकृत और सत्यापित परिवार आधारित डाटाबेस तैयार करने की पहल की है। इस प्रस्तावित व्यवस्था के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार का पंजीकरण किया जाएगा और उस परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की सबसे वरिष्ठ महिला सदस्य को परिवार का मुखिया माना जाएगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल परिवारों की पहचान स्पष्ट होगी, बल्कि महिलाओं की भूमिका को भी अधिक सम्मान और महत्व मिलेगा।

प्रदेश सरकार की इस पहल को महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। परंपरागत रूप से कई सरकारी दस्तावेजों में परिवार का मुखिया पुरुष को माना जाता रहा है, लेकिन इस नई व्यवस्था के तहत परिवार की वरिष्ठ महिला को प्राथमिकता देकर राज्य सरकार ने समाज में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करने का संदेश दिया है।

सरकार का कहना है कि "देवभूमि परिवार" प्रणाली के लागू होने के बाद राज्य के विभिन्न विभागों में बिखरे हुए लाभार्थी आंकड़ों को एक ही मंच पर लाया जाएगा। इससे योजनाओं के संचालन में पारदर्शिता बढ़ेगी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं सरल होंगी। अभी तक कई विभाग अपने-अपने स्तर पर अलग-अलग डाटाबेस का उपयोग करते हैं, जिससे कई बार रिकॉर्ड का दोहराव, बार-बार सत्यापन की जटिल प्रक्रिया और विभागों के बीच समन्वय की कमी जैसी समस्याएं सामने आती हैं। नई व्यवस्था के लागू होने के बाद सरकार के पास राज्य के प्रत्येक परिवार की एक स्पष्ट और प्रमाणित जानकारी उपलब्ध होगी। इससे यह सुनिश्चित करना आसान होगा कि किस परिवार को कौन-कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है और किसे अभी लाभ मिलना बाकी है। इस तरह योजनाओं का लाभ अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत तरीके से पात्र लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा। धामी सरकार का यह भी मानना है कि एकीकृत डाटाबेस बनने से भविष्य में नई योजनाओं की योजना बनाने और उन्हें लागू करने में भी मदद मिलेगी। जब सरकार के पास राज्य के परिवारों से जुड़ा सटीक और प्रमाणित डाटा होगा, तब नीतियां बनाना अधिक आसान और प्रभावी हो जाएगा। बता दें कि इस प्रकार की प्रणाली से सरकारी योजनाओं में होने वाली अनियमितताओं और गड़बड़ियों को भी काफी हद तक रोका जा सकेगा। साथ ही यह व्यवस्था राज्य के प्रशासनिक ढांचे को और अधिक मजबूत बनाने में भी सहायक सिद्ध हो सकती है। देवभूमि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में जहां कई दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों तक योजनाओं को पहुंचाना एक बड़ी चुनौती होती है, वहां इस तरह का एकीकृत डाटाबेस सरकार और प्रशासन के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है। इससे दूरदराज के गांवों में रहने वाले लोगों तक भी योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी तरीके से पहुंचाया जा सकेगा।

धामी

सरकार की इस पहल को राज्य में डिजिटल प्रशासन और सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भी देखा जा रहा है। "देवभूमि परिवार" प्रणाली के माध्यम से राज्य सरकार प्रशासनिक कार्यों को अधिक आधुनिक और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

देवभूमि परिवार योजना में किन लोगों को मिलेगा लाभ

उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रस्तावित "देवभूमि परिवार विधेयक-2026" का उद्देश्य राज्य के हर परिवार की एकीकृत पहचान तैयार करना है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से लोगों तक पहुंच सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लाई गई इस पहल के तहत राज्य के सभी परिवारों का एक केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जिसे "देवभूमि परिवार" नाम दिया गया है। इस योजना के तहत मुख्य रूप से उत्तराखंड के स्थायी निवासी परिवार पात्र माने जाएंगे। ऐसे परिवार जो राज्य में निवास करते हैं और जिनके पास वैध पहचान तथा निवास से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध हैं, उन्हें इस डेटाबेस में शामिल किया जाएगा। प्रत्येक परिवार को एक इकाई के रूप में दर्ज किया जाएगा और परिवार के सभी सदस्यों का विवरण इस प्रणाली में जोड़ा जाएगा। योजना में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के परिवारों को शामिल करने का प्रावधान रखा गया है। पर्वतीय गांवों में रहने वाले लोग, शहरों और कस्बों के निवासी, किसान परिवार, श्रमिक वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार और अन्य सामान्य परिवार भी इस डेटाबेस का हिस्सा बन सकेंगे।

इसके अलावा नीति विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे लोग भी इस व्यवस्था में शामिल हो सकते हैं जो लंबे समय से उत्तराखंड में निवास कर रहे हैं और राज्य की सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था का हिस्सा बन चुके हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई परिवार पिछले कई वर्षों से राज्य में रह रहा है और स्थानीय प्रशासन के रिकॉर्ड में दर्ज है, तो उसे भी इस प्रणाली में शामिल किया जा सकता है। कई मामलों में 15 वर्ष या उससे अधिक समय से राज्य में रह रहे परिवारों को स्थानीय दस्तावेजों के आधार पर निवास से जुड़ी श्रेणियों में शामिल किया जाता रहा है, हालांकि अंतिम पात्रता का निर्धारण सरकार के नियमों और सत्यापन प्रक्रिया के आधार पर होगा। "देवभूमि परिवार" डेटाबेस बनने के बाद सरकार के पास प्रत्येक परिवार से जुड़ी एक समेकित जानकारी उपलब्ध होगी। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि किस परिवार को कौन-कौन सी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल चुका है और किन परिवारों तक अभी योजनाओं का लाभ पहुंचाना बाकी है।

सरकार का मानना है कि यह प्रणाली भविष्य में योजनाओं के संचालन को अधिक पारदर्शी, तेज और प्रभावी बनाएगी तथा देवभूमि के हर घर को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

मिलावटखोरी का बढ़ता बाजार जिम्मेदार कौन?

कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में व्यापारियों के लिए कम तौलने की अनेक विधियां बतलायी है लेकिन खाद्य उत्पादों में मिलावट की बात कहीं भी नहीं की है क्योंकि कम तौलने से मानव स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं है जबकि मिलावट के कारण जान भी जा सकती है। आजकल बड़े खतरनाक ढंग से खाद्य उत्पादों में मिलावट की खबरें आ रही है। दूध में पानी मिलाने की घटनाएं तो आम तथा अपेक्षाकृत कम नुकसानदेय है परन्तु आजकल तो दूध में डिटरजेंट, यूरिया, कास्टिक सोडा या तेल जैसी हानिकारक पदार्थों की मिलावट हो रही है जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत ही खतरनाक है। ठीक इसी तरह देशी घी में वनस्पति घी की मिलावट, लाल मिर्च में ईंट क चूरा या लकड़ी का बुरादा, हल्दी में मेटानिक येलो कलर, चाय की पत्ती में लोहे के कण, मिठाई या मावे में मैदे की मिलावट, सरसो के तेल में आर्जीमोन या पॉम ऑयल की मिलावट आज आम बात हो गई है। खाद्य उत्पादों में होने वाली इसी मिलावट को आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चढ्ढा ने संसद में उठाया है लेकिन सवाल यहां यह उठता है कि मिलावटखोरी के इस कृत्य के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है?

प्रोग्रेसिव डेरी फारमर्स एसोसिएशन उत्तराखंड के अध्यक्ष, सुबोध कुमार कहते हैं कि खाद्य उत्पादों में हो रही मिलावट के लिए कहीं न कही ग्राहक भी जिम्मेदार है। क्योंकि ग्राहक हमेशा रेट पर कम्प्रोमाईस कर लेता है जिसके कारण मिलावटी खाद्य उत्पादों के सामने असली खाद्य उत्पादों को टिकने में मुश्किलों का सामना करना पडता है। जैसे एक गाय से दूध उत्पादन के खर्च के हिसाब से आज के समय में दूध का रेट करीब 60 रू. लीटर होता है लेकिन मार्केट में आपको मिलावटी दूध 45 से 50 रू0 लीटर भी मिल जाता है। रेट में होने वाला यही अन्तर मिलावट होता है। ग्राहक को किसान के प्रति विश्वास पैदा करना होगा, उसे उसकी मेहनत का मूल्य अदा करके मजबूत बनाने का प्रयास करना होगा। सरकार चाहे कितना भी प्रयास कर ले जब तक ग्राहक जागरूक नहीं होगा तब तक मार्किट से मिलावट खत्म नहीं होगी।

फीमेल न्यूट्रिशन एक्सपर्ट एवं डायटीशियन वंदना का कहना है कि आजकल बाजार में सिर्फ मसालों में ही नहीं बल्कि भरोसे में भी मिलावट होने लगी है। ग्राहक जब बार-बार मिलावटी सामान की खबरें सुनता है तो शॉप पर जाते ही उसके दिमाग में एक छोटा सा ''संदेह का अलार्म'' बजने लगता है। वह पैकेट को ऐसे देखता है जैसे कोई जासूस सुराग ढूंढ रहा हो। कभी लेबल पढ़ता है कभी दुकानदार को घूरकर पूछता है-भाई साहब यह सच में शुद्ध है ना? इस माहौल में जो लोग सच में बिना मिलावट का सामान बेचते है उन्हें भी खुद को साबित करना पड़ता है। उन्हें अब सिर्फ सामान नहीं बल्कि ईमानदारी और भरोसा भी पैक करके बेचना होता है। लेकिन एक मजेदार बात है-जहां ग्राहक को असली और शुद्ध चीज मिल जाती है वहीं वह पक्का ग्राहक बन जाता है क्योंकि आज के दौर में सबसे बड़ी मार्केटिंग यही है- ''शुद्धता का स्वाद और भरोसे की खुशबू''

प्रमुख आटा व्यवसायी मुणाल गोयल का कहना है कि मिलावटखोरी दरअसल पूरी तरह से व्यक्ति के माइंड से जुडा मसला होता है। जहां कुछ लोग अपने उसूलों से समझौता न करके ग्राहक को अच्छा सामान उपलब्ध कराते है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग होते है जो ज्यादा मुनाफे के लालच में ग्राहक के स्वास्थ्य से खिलवाड करने में भी नहीं चूकते। जब ग्राहक किसी सामान की पूरी कीमत देने को तैयार रहता है तब व्यवसायी की जिम्मेदारी होती है कि वे ग्राहक को अच्छी क्वालिटी का सामान ही उपलब्ध कराएं।

सिलक्यारा ब्रांड के फाउंडर लोकेश राज अस्थाना कहते है कि कम लागत ज्यादा मुनाफा ही वो सोच है जो मिलावटखोरी को बढावा देती है। ग्राहक तो असली खाद्य उत्पादों की ही कीमत चुकाता है लेकिन जरा से मुनाफे के लालच के चलते कुछ लोग न केवल ग्राहक से उत्पादों की पूरी कीमत वसूल कर उन्हें घटिया किस्म के मिलावटी खाद्य उत्पाद बेच देते है बल्कि आम लोगों के स्वास्थ्य से भी खिलवाड कर रहे है। मिलावटखोरों के द्व ारा किये जाने वाले इन कृत्यों का सीधा असर असली खाद्य उत्पादों का व्यापार करने वाले लोगों पर भी होता है। मिलावटखोरी के प्रति लोगों को खुद भी जागरूक होना पडेगा और देखना होगा कि अगर किसी उत्पाद की वास्तविक लागत ही 100 रू० है तो विक्रेता उसको 80 रू० में कैसे बेच रहा है? सरकार तो मिलावटखोरी की तरफ विशेष ध्यान दे ही साथ में लोग भी मिलावटखोरी के प्रति अपनी आवाज उठाएं तथा हमेशा अच्छी क्वालिटी के ही खाद्य उत्पाद उपयोग में लाएं।

मिलावटखोरों पर और कसेगा सरकार का शिकंजा

हर माह एक सप्ताह का विशेष अभियान चलेगा, स्टाफ की कमी भी होगी दूर

जनस्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों पर धामी सरकार का शिकंजा अब और कसेगा। त्योहारों के समय ही नहीं, बल्कि हर माह में एक सप्ताह खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने के लिए विशेष अभियान चलेगा। इसके अलावा, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में स्टाफ की कमी को भी दूर किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई बख्शा न जाए।

हर महीने अभियान, हाट-मेलों पर खास ध्यान: विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन बृहस्पतिवार को सरकार ने साफ किया कि खाद्य पदार्थों की जांच का काम तेजी से चल रहा है। इसकी गति और तेज की जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि हाट-मेलों में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को खास तौर पर चेक किया जाएगा।

खाद्य पदार्थों की जांच-दो वर्ष का हिसाब

वर्ष 2023-24: इस वर्ष में खाद्य पदार्थों के कुल 1627 नमूने लिए गए, जिसमें से 171 फेल हुए। इसके आधार पर 171 वाद पंजीकृत कराए गए।

वर्ष 2024-25: इस वर्ष में खाद्य पदार्थों के 1684 नमूने लिए गए, जिसमें से 159 फेल हुए। इस आधार पर 159 वाद दायर किए गए।

दूर होगी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की कमी: प्रदेश में वर्तमान में 28 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की कमी है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार ने लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा है। सरकार का कहना है कि आयोग से भर्ती प्रक्रिया में यदि देर होती है, तो प्रतिनियुक्ति के जरिये भी इन पदों को भरने का प्रयास किया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के खाली पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए सरकार प्रयासरत है। उन्होंने यह भी बताया कि देहरादून में टेस्टिंग लैब का कार्य 31 मार्च 2026 तक पूरा हो जाएगा।

जंग का असर रसोई तक, देश में गैस सिलेंडर की मारामारी

मध्य-पूर्व में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध तनाव का असर भारत की रसोई तक पहुंच गया है। गैस सप्लाई प्रभावित होने से देश के कई राज्यों में एलपीजी सिलेंडर की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लग रही हैं और लोगों को सिलेंडर के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। बढ़ते संकट को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। संसद भवन, नई दिल्ली में कांग्रेस सांसदों ने गैस संकट को लेकर प्रदर्शन किया, जबकि गैरसैंण में चल रहे उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भी कांग्रेस विधायकों ने विरोध दर्ज कराया। देश के कई हिस्सों में गैस की कमी से आम लोगों की रसोई पर सीधा असर पड़ रहा है। दिव्य हिमगिरि रिपोर्ट।

मध्य-पूर्व में बढ़ते युद्ध तनाव का असर अब भारत के आम लोगों की रसोई तक पहुंचने लगा है। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच जारी टकराव के कारण खाड़ी क्षेत्र में तेल और गैस की सप्लाई चेन प्रभावित हो गई है। खास तौर पर हॉर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ा है। इसी का असर भारत में भी दिखाई देने लगा है, जहां कई राज्यों में एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत के कारण लोग परेशान हैं और गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लग रही हैं। देश के कई हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां लोग सुबह से गैस एजेंसियों के बाहर लाइन लगाकर सिलेंडर मिलने का इंतजार कर रहे हैं। कई जगहों पर गैस एजेंसियों के फोन नहीं लग रहे हैं और ऑनलाइन बुकिंग में भी दिक्कतें सामने आ रही हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को घरेलू कामकाज चलाने के लिए वैकल्पिक साधनों की तलाश करनी पड़ रही है। उत्तराखंड में भी गैस संकट का असर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। राज्य के कई शहरों और कस्बों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए यह संकट और भी गंभीर बनता जा रहा है, क्योंकि वहां पहले से ही सप्लाई सीमित रहती है। इस मुद्दे को लेकर उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान गैरसैंण में विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायकों ने गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर विधानसभा के बाहर और सदन के भीतर विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस का आरोप है कि गैस संकट के कारण आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और सरकार को इस पर तत्काल ठोस कदम उठाने चाहिए। उधर राष्ट्रीय स्तर पर भी यह मुद्दा राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। संसद भवन, नई दिल्ली में कांग्रेस सांसदों ने गैस संकट को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। विपक्ष का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय हालात का असर भारत पर पड़ना स्वाभाविक है, लेकिन सरकार को पहले से तैयारी करनी चाहिए थी ताकि आम लोगों को इतनी परेशानी न झेलनी पड़े। गैस संकट के बीच देश के कई हिस्सों में कालाबाजारी और जमाखोरी की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। कई शहरों में जहां कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत करीब दो हजार रुपये होती है, वहां इसे चार हजार रुपये तक में बेचे जाने की खबरें सामने आई हैं। प्रशासन ने ऐसे मामलों पर निगरानी बढ़ा दी है, लेकिन संकट के

कारण बाजार में अस्थिरता बनी हुई है। ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुसार इस संकट की सबसे बड़ी वजह हॉर्मुज जलडमरूमध्य का बंद होना है। यह लगभग 167 किलोमीटर लंबा समुद्री मार्ग है, जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया के कुल पेट्रोलियम व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, इराक और कुवैत जैसे प्रमुख तेल उत्पादक देश अपने निर्यात के लिए इसी मार्ग पर निर्भर रहते हैं। भारत भी अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से पूरा करता है। अनुमान के अनुसार भारत करीब 50 प्रतिशत कच्चा तेल और 50 प्रतिशत से अधिक एलएनजी इसी रास्ते से आयात करता है। ऐसे में इस मार्ग के बंद होने से भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव बढ़ना स्वाभाविक है। इसी कारण देश में एलपीजी की मांग अचानक बढ़ गई है। सामान्य दिनों में जहां प्रतिदिन लगभग 50 से 55 लाख गैस बुकिंग होती थी, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 75 से 76 लाख तक पहुंच गई है। इस स्थिति को ऊर्जा क्षेत्र के जानकार "पैनिक बुकिंग" का परिणाम भी मान रहे हैं, जिसमें लोग भविष्य की आशंका के कारण जरूरत से पहले ही सिलेंडर बुक कर रहे हैं।

गैस संकट के बीच केंद्र सरकार अलर्ट, कई बड़े कदम उठाए

गैस संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने स्थिति पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव (मार्केटिंग एवं ऑयल रिफाइनरी) सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी की उपलब्धता फिलहाल चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि भारत का बड़ा हिस्सा आयात हॉर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते आता है, जो फिलहाल प्रभावित है। उन्होंने यह भी कहा कि संकट को नियंत्रित करने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है और घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने सबसे पहले तेल कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है, जो देश में गैस की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की लगातार समीक्षा कर रही है। इस समिति में तीन प्रमुख तेल कंपनियों के कार्यकारी निदेशक शामिल हैं और इन्हें स्थिति पर निगरानी रखने तथा आवश्यक निर्णय लेने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने गैस की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत प्रशासन को अधिकार दिया गया है कि वह जमाखोरी या अवैध बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। घरेलू एलपीजी बुकिंग के नियमों में भी बदलाव किया गया है। पहले जहां सिलेंडर डिलीवरी के कुछ ही दिनों बाद नया सिलेंडर बुक किया जा सकता था, वहीं अब उपभोक्ताओं को अगली बुकिंग के लिए कम से कम 25 दिन का इंतजार करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में यह अवधि बढ़ाकर 45 दिन तक कर दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे अनावश्यक बुकिंग और जमाखोरी पर रोक लगेगी। इसके साथ ही गैस सिलेंडर की डिलीवरी के समय ओटीपी या बायोमेट्रिक सत्यापन को अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सिलेंडर सही उपभोक्ता तक ही पहुंचे। इससे फर्जी बुकिंग और अवैध बिक्री को रोकने में मदद मिलने की उम्मीद है। सरकार ने देश की सभी ऑयल रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। इन निर्देशों के बाद उत्पादन में करीब 28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार का दावा है कि इससे आने वाले दिनों में स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है। गैस संकट का असर बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। कई शहरों में लोग एलपीजी के विकल्प के तौर पर इंडक्शन कुकटॉप और इलेक्ट्रिक चूल्हों की ओर रुख कर रहे हैं। इसके कारण ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर इन उत्पादों की मांग अचानक बढ़ गई है। कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इंडक्शन कुकटॉप के कई मॉडल आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं। मध्य-पूर्व में तनाव जल्द कम नहीं हुआ तो ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बनी रह सकती है। इसका असर केवल गैस सिलेंडर ही नहीं, बल्कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों और अन्य ऊर्जा स्रोतों पर भी पड़ सकता है। फिलहाल देशभर में आम लोग इस संकट से जूझ रहे हैं और सरकार की कोशिश है कि सप्लाई व्यवस्था को जल्द सामान्य किया जाए। उत्तराखंड सहित कई राज्यों में प्रशासन ने गैस एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि वे वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाएं और लोगों को अनावश्यक परेशानी न होने दें। हालांकि अंतरराष्ट्रीय हालात को देखते हुए विशेषज्ञ मानते हैं कि स्थिति पूरी तरह सामान्य होने में कुछ समय लग सकता है। तब तक सरकार और प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि देश के हर घर की रसोई तक गैस की आपूर्ति सुचारु रूप से बनी रहे।

गैस संकट पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा- घबराने की जरूरत नहीं, आपूर्ति सुचारु रखने के निर्देश

उत्तराखंड में रसोई गैस सिलेंडर की किल्लत की खबरों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और आम लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण गैस सप्लाई पर कुछ दबाव जरूर पड़ा है, लेकिन राज्य सरकार केंद्र सरकार और तेल कंपनियों के साथ लगातार समन्वय बनाकर आपूर्ति व्यवस्था को सामान्य बनाए रखने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी जिलों में गैस की उपलब्धता की नियमित निगरानी की जाए और जहां कहीं भी आपूर्ति में बाधा की स्थिति बन रही हो, वहां तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने विशेष रूप से पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों पर ध्यान देने को कहा है, ताकि वहां रहने वाले लोगों को गैस सिलेंडर की कमी का सामना न करना पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि गैस की कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। यदि कहीं भी अधिक कीमत पर सिलेंडर बेचने या अवैध भंडारण की शिकायत मिलती है तो संबंधित लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक घबराहट में गैस सिलेंडर की अतिरिक्त बुकिंग न करें। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार स्थिति की समीक्षा कर रही है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त आपूर्ति की व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि प्रदेश के हर घर की रसोई सुचारु रूप से चलती रहे।

करोड़ों खर्च, फिर भी क्यों प्रदूषित हो रहा है जल

डॉ. हरीश चन्द्र अन्डोला

जीवन के लिए पानी 'अमृत' समान है। यह लोगों की बुनियादी जरूरत है। शहरीकरण और औद्योगीकरण ने काफी हद तक इसकी गुणवत्ता को प्रभावित किया है। ग्राउंड वाटर लेवल भी साल दर साल नीचे जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश के 60 करोड़ लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं जबकि 16 करोड़ लोग गंदा पानी पी रहे हैं। शुद्ध पानी के लिए सरकार करोड़ों-अरबों रुपये खर्च कर रही है, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। देश के करीब 9 राज्यों में पानी की गुणवत्ता खराब है। यहां नाइट्रेट, फ्लोराइड, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, निकेल, कोबाल्ट जैसे तत्व मानक से अधिक पाए गए हैं। खराब पानी की वजह से काफी लोगों की मौत भी चुकी है। काफी लोग तमाम बीमारियों से जूझ रहे हैं।

केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 जारी की। इसमें देशभर में ग्राउंड वाटर क्वालिटी का पता लगाने के लिए 2023 को बेस ईयर मानकर कुल 15,259 सैंपल इकट्ठा किए गए। साल 2025 में 5 हजार 368 स्टेशनों से ये नमूने लिए गए। इनमें से कुछ मानसून से पहले जबकि कुछ मानसून के बाद के थे। इनकी जांच अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन में दिए गए स्टैंडर्ड तरीकों से कराई गई। जांच के पीछे का मकसद पीने और खेती के लिए इस्तेमाल होने पानी की गुणवत्ता को अलग-अलग पैरामीटर पर परखना था। जांच में कई राज्यों के पेयजल शुद्ध पाए गए जबकि कई स्टेट में ये काफी प्रदूषित मिले।

शुद्ध पेयजल के मानक क्या हैं?, देश की कितनी आबादी दूषित पानी से परेशान है?, ग्राउंड वाटर लेवल साल दर साल नीचे क्यों जा रहा है?, विश्व के अन्य कौन से देश दूषित पेयजल का सामना कर रहे हैं। सरकार वाटर क्वालिटी को सुधारने के लिए क्या उपाय कर रही है? जांच में अरुणाचल, मिजोरम, मेघालय और जम्मू कश्मीर के 100% नमूने भारतीय मानक ब्यूरो के अनुरूप पाए गए। यानी यहां का पानी पूरी तरह शुद्ध है। लिहाजा ये पीने और फसलों की सिंचाई के लिए काफी उपयुक्त है। यहां के लोगों को दूषित पानी से होने वाली बीमारियों को लेकर फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। कम आबादी और कम औद्योगीकरण के कारण यहां पानी की गुणवत्ता ठीक है। इन राज्यों में इंडस्ट्रियल कचरे और शहरी प्रदूषण का दबाव कम है। मानसून में होने वाली ज्यादा बारिश सतह और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में मदद करती है। यहां सीमित खेती होती है। मतलब फर्टिलाइजर/पेस्टीसाइड का प्रयोग कम किया जाता है। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में नाइट्रेट मानक से अधिक पाया गया। लवणता भी ज्यादा मिली। पूर्वी राज्य यानी असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम आदि और उत्तर-पूर्वी राज्यों में आयरन, मैंगनीज और आर्सेनिक पाए गए हैं। कुल 9 राज्यों में पानी की गुणवत्ता खराब है। साफ पानी को लेकर ये प्रदेश हाई रिस्क पर माने गए हैं।

जांच में यह पता चला कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश दूषित पानी से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। यहां नाइट्रेट, फ्लोराइड, आर्सेनिक, यूरेनियम और खारेपन की मात्रा बहुत ज्यादा है। राजस्थान, हरियाणा और आंध्र प्रदेश के पानी में भी काफी गंदगी नजर आती है। पंजाब और गुजरात के भी हालात ठीक नहीं हैं। पानी में आर्सेनिक का होना काफी समय से चिंता का विषय है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जिन जमीनों से होकर गुजरती हैं, खास तौर पर वहां यह समस्या ज्यादा है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में भी कभी-कभार यूरेनियम मानक से ज्यादा पाए गए हैं।

असम, कर्नाटक, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे कई राज्यों के पानी में गैंगनीज की मात्रा ज्यादा पाई गई है। वहीं पूरे देश में कॉपर का लेवल लगातार तय लिमिट के अंदर पाया गया। भारत में ग्राउंड वाटर लेवल कई वजहों से लगातार कम हो रहा है। सिंचाई के लिए ज्यादा पानी निकालना भी इनमें से एक है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में धान और गन्ने जैसी फसलों की सिंचाई के लिए जमीन से ज्यादा पानी निकाला जाता है। दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों में शहरी मांग बढ़ रही है। यहां तेजी से कंस्ट्रक्शन और पक्की सड़कों की वजह से भूजल प्राकृतिक रूप से रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा मौसम में बदलाव, अनियमित मानसून, देर से बारिश और सूखे की वजह से भी दिक्कत आ रही है। शहरी और इंडस्ट्रियल जोन के बढ़ने से जमीन तक पानी का रिसाव रुक जाता है। फ्लोराइड, नाइट्रेट और आर्सेनिक प्रदूषण के कारण लोगों को गहरे कुएं खोदने पड़ते हैं। इससे तेजी से पानी खत्म हो रहा है। समय करीब 30 शहर गंदे पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। साल 2050 तक यहां पानी काफी दूषित हो जाएगा। इन शहरों में जयपुर, इंदौर, कोलकाता, जालंधर, अहमदाबाद, पुणे, ठाणे, जबलपुर, धनबाद, वड़ोदरा, मुंबई, भोपाल, श्रीनगर, लखनऊ, ग्वालियर, राजकोट, हुबली-धारवाड़, सूरत, कोटा, नागपुर, दिल्ली, नासिक, चंडीगढ़, अलीगढ़, विशाखापट्टनम, अमृतसर, कोझिकोड, बेंगलुरु, लुधियाना, कन्नूर शामिल हैं।उत्तर प्रदेश के पवित्र गंगा नदी में इंडस्ट्रियल गंदगी, बिना ट्रीट किया

हुआ घरेलू सीवेज और खेती से निकला पानी मिलकर उसे दूषित बना रहा है। कई जगहों पर पेयजल के दूषित होने का भी यही कारण है। महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की वजह से मीठी और गोदावरी नदियों में प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है। इसी तरह दिल्ली में बार-बार सफाई के बावजूद यमुना नदी बहुत ज्यादा गंदी है। इसमें बिना ट्रीट किए सीवेज और शहरों से निकलने वाला गंदा पानी पहुंचता है। भारत के बड़े इंडस्ट्रियल पावर हाउस में से एक गुजरात भी खराब पानी की चुनौतियों का सामना कर रहा है। फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रियल क्लस्टर से निकलने वाला केमिकल कचरा, टेक्सटाइल डाई और हेवी मेटल सतही और ग्राउंड वाटर सोर्स में पहुंच रहे हैं। पंजाब में खेती से निकलने वाला फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का बहाव पानी को दूषित कर रहा है। छोटी इंडस्ट्रीज से निकलने वाला गंदे पानी ने ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट का लेवल बढ़ा दिया है। भारत की अभी की आबादी लगभग 142.59 करोड़ है। 2025-26 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा खराब पानी की समस्या का सामना कर रहा है। देश के करीब 60 करोड़ लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा है। जबकि 16 करोड़ लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। मौजूदा समय में लगभग 70% पानी के सोर्स खराब हैं। करीब 20 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे पानी के संपर्क में हैं जिनमें आर्सेनिक और फ्लोराइड जैसे केमिकल मानक से ज्यादा हैं। जनवरी 2025 और जनवरी 2026 के बीच 26 शहरों में सीवेज का गंदा पानी नल में मिल गया। इसकी वजह से करीब 5500 लोग बीमार पड़ गए। 3.77 करोड़ लोग हर साल पानी से होने वाली बीमारियों से प्रभावित होते हैं। दिल्ली, पटना और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में 40 साल पुराने पाइपों का सीवेज में मिलना सिर्फ मानसून की समस्या नहीं है, बल्कि यह साल भर की समस्या है। नीति आयोग की साल 2018 की रिपोर्ट के अनुसार साफ पानी की कमी से हर साल देश में लगभग 2 लाख लोगों की मौत होती है। मौजूदा माइक्रोबायोलॉजी स्टडीज के अनुसार यह देखा गया कि एक्यूट डायरिया डिजीजटाइफाइड, हैजा, हेपेटाइटिस और शिगेलोसिस भारत में पानी से होने वाली आम बीमारियां हैं। इनसे 2014 और 2018 के बीच लगभग 11,728 मौतें हुईं। इनमें 10,768 मौतें 2017 के बाद की हैं। गंदे पानी से हैजा, डायरिया, पेचिश, हेपेटाइटिस, टाइफाइड और पोलियो जैसी बीमारियों का खतरा रहता है। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां भी हो सकती हैं। खराब पानी पीने या मछली समेत झींगा, केकड़ा आदि खाने से माइक्रोप्लास्टिक भी शरीर के अंदर पहुंच जाता है। 2020 की एक स्टडी रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि इंसान हर सप्ताह करीब 0.1 से 5 ग्राम माइक्रोप्लास्टिक खा लेता है। इसी तरह आर्सेनिक मिले पानी से हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और लीवर प्रभावित होते हैं। लंबे समय तक आर्सेनिक के संपर्क में रहने पर स्किन में हाइपरकेराटोसिस, हाइपरपिग्मेंटेशन और हाइपोपिग्मेंटेशन जैसे रोग लग जाते हैं। तंत्रिका तंत्र को भी नुकसान पहुंचता है। डब्लुएचओ के मुताबिक हर साल दुनिया में लगभग 14 लाख लोग खराब सफाई, खराब हाइजीन या खराब पानी पीने से मर जाते हैं। लोगों को शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। जल जीवन मिशन (हर घर जल) के तहत अब 81% ज्यादा ग्रामीण ों के घरों में साफ पानी पहुंच रहा है। 22 अक्टूबर 2025 तक 15.72 करोड़ से ज्यादा लोगों को घरेलू नलों से साफ पानी मिला। मिशन के तहत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2,08,652 करोड़ दिए। इसकी ज्यादातर रकम का इस्तेमाल हो चुका है। इसके अलावा ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाने, पानी को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए अन्य तरीके से भी काफी रुपये खर्च किए जा रहे हैं। भारत के अलावा दुनिया के अन्य भी कई देश दूषित पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। चाड, केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य, लिसोटो समेत कई देशों के लोगों को खराब गुणवत्ता वाले पेयजल का सामना करना पड़ रहा है। यहां भी दूषित पानी से कई तरह की बीमारियां हो रहीं हैं। जबकि फिनलैंड, जर्मनी समेत कई देशों का पानी उच्च गुणवत्ता वाला है। दूषित पानी के मामले में दुनिया में भारत की रैंक 144 है, जबकि स्कोर 25.5 है। पृथ्वी की सतह का लगभग 71 प्रतिशत हिस्सा पानी से ढका हुआ है। हालांकि, 97 प्रतिशत पानी समुद्री है। 3 प्रतिशत पानी ही मीठा है जिसे फ्रेश वाटर भी कहा जाता है। अगर इस 3 प्रतिशत पानी में ही जहर घुलने लगे तो क्या होगा। इंदौर में पानी की वजह हुई मौतों ने एक बार फिर साफ पानी का मुद्दा उठा दिया है। हालांकि, ये भारत या पूरी दुनिया में पहली बार नहीं हुआ। पानी की वजह से रोजाना कई जिंदगिया खत्म हो रही हैं। अगर गंगा नदी में गंदगी ना गिराई जाए तो इसे निर्मल बनाए रखना असंभव नहीं है। लेकिन होता है इसके उलटा। कई जगह गंदगी को गंगा में सीधे बहा दिया जाता है। नदी के किनारे शवों को जलाया जाता है। खतरनाक जीवाणुओं और जैव रासायनिक तत्वों की अत्यधिक मात्रा से गंगा नदी का पानी काफी प्रदूषित हो गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बीते मार्च महीने में ऋषिकेश से लेकर हावड़ा तक यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 94 जगहों से गंगा जल का सैंपल लिया था। प्रदूषण का हाल यह था कि कानपुर में तेनुआ (ग्रामीण) के पास प्रति सौ मिलीग्राम जल में टोटल कोलीफॉर्म (टीसी) जीवाणुओं की संख्या 33 हजार के पार थी, जबकि यह संख्या अधिकतम 5000 होनी चाहिए थी। हालत यह कि गंगा नदी के पानी को पीना तो दूर, उससे नहाना भी मुश्किल है। सुकून की बात है कि रिपोर्ट के अनुसार ऑक्सीजन की मात्रा मानक से कम नहीं है। बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार देश में चार जगहों, ऋषिकेश (उत्तराखंड), मनिहारी व कटिहार (बिहार) एवं साहेबगंज व राजमहल (झारखंड) में गंगा के पानी को ग्रीन कैटेगरी में रखा गया है। अर्थात इन जगहों के पानी से किटाणुओं को छान कर पीने में इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी सभी जगह रेड कैटेगरी में रखे गए हैं। नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत 31 मार्च, 2021 तक गंगा और उसकी सहायक नदियों को स्वच्छ बनाने के लिए 20,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ जून, 2014 में शुरू की गई थी। केंद्रीय मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने बीते फरवरी माह में राज्य सभा में लिखित उत्तर में बताया था कि केंद्र सरकार द्वारा एनएमसीजी (नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा) को वित्तीय वर्ष 2014-15 से 31 जनवरी, 2023 तक 14084.72 करोड़ रिलीज किए जा चुके हैं। वहीं 31 दिसंबर, 2022 तक 32,912.40 करोड़ की लागत से कुल 409 प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया जिनमें से 232 प्रोजेक्ट को पूरा कर चालू कर दिया गया है। अब 2026 तक के लिए 22500 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान के साथ नमामि गंगे मिशन-2 को केंद्र सरकार ने अपनी स्वीकृति दी है। यह बात दीगर है कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट ने कई महत्वपूण र्ा आयाम हासिल किए हैं, परिदृश्य बदलेगा भी। लेकिन, यह भी कटु सत्य है कि जनभागीदारी के बगैर गंगा नदी की अविरलता व निर्मलता सुनिश्चित नहीं की जा सकेगी।

लेखक विज्ञान व तकनीकी विषयों के जानकार दून विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं।

संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय लोक जीवन से जुड़ा है - लीलाधर जगूड़ी

दून पुस्तकालय में नवोदित प्रवाह लोक संस्कृति विशेषांक का लोकार्पण

दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र, देहरादून के तत्वावधान में केंद्र के सभागार में आयोजित समारोह मेंरजनीश त्रिवेदी द्वारा संपादित साहित्यिक पत्र नवोदित प्रवाह के लोक संस्कृति विशेषांक का भव्य लोकार्पण साहित्यकारों द्वारा किया गया। लोकार्पण के पश्चात लोक संस्कृति पर विमर्श भी किया गए। समारोह के मुख्य अतिथि साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित देश के वरिष्ठ कवि और साहित्यकार पद्मश्री लीलाधर जगूड़ी थे जबकि अध्यक्षता राज्य की मुख्य सूचना आयुक्त राधा रतूड़ी ने की। लोकार्पण के उपरांत लोक संस्कृति विमर्श में वरिष्ठ लेखक अनिल रतूड़ी, पद्मश्री माधुरी बड़थ्वाल, गीतकार डॉ. रामविनय सिंह, श्री नौटियाल ने भाग लिया। मुख्य अतिथि लोकार्पित विशेषांक अत्यधिक वैदुष्यपूर्ण और संग्रहणीय है। उन्होंने विशेषांक में प्रकाशित कविताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि आज के समय में कविताएं लिखने वाले ऐसे कवि दुर्लभ हो गये हैं जो भाषा में शब्दों को लेकर अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति नये ढंग से कर सकें। उन्होंने कहा कि सबसे पहले प्राकृत कविताओं का स्मरण इस अंक को देखते ही हो जाता है। पता चल जाता है कि कविता ने अपने कितने बौद्धिक घराने बदले हैं। विशेषांक में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तथा गुजरात से पूर्वोत्तर असम, अरुणाचल, नागा लोक संस्कृति की प्रस्तुति अत्यंत रोचकता के साथ प्रस्तुत की गई है उत्तराखण्ड के कुमाऊनी, गढ़वाली,तथा जौनसारी जीवन पद्धति का स्मरण कराने वाले विवेचन प्रस्तुत किये गये हैं। प्रसिद्ध कुमाऊनी झोड़ा का संस्कृत भावानुवाद प्रस्तुत किया गया है।

लीलाधर जगूड़ी ने कहा कि आजकल ऐसी विद्वतापूर्ण पत्रिका का प्रकाशन में एक अद्भुत संयोग ही नहीं बल्कि विलक्षण घटना मानता हूँ इसमें डॉ. गिरिजा शंकर त्रिवेदी जी की कविता 'कोई घर आने वाला है' देखकर तो मुझे पूरा अतीत याद आ गया। उन्होंने कहा कि लोक संस्कृति विशेषांक में पाली साहित्य में लोक संस्कृति से लेकर भारत की लगभग सभी भाषाओं के साहित्य की प्रवृत्तियों और रचनाकारों के माध्यम से भारतीय लोक संस्कृति की विवेचना प्रस्तुत की गई है। उन्होंने डॉ. सुधा पाण्डे के पाली साहित्य पर लेख को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया जो हमें बौद्ध साहित्य के अंतर्गत त्रिपिटक और थेर गाथाओं में आध्यात्म के साथ साथ भिक्षु नाग सेन और मिलिंद के संवादों की भी स्मृति दिलाता है।

समारोह के मुख्य वक्ता पूर्व पुलिस महानिदेशक व साहित्यकार अनिल रतूड़ी ने लोक संस्कृति विशेषांक का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया और कहा साहित्यिक पत्रिका 'नवोदित प्रवाह' 2026, वार्षिक अंक में लोक संस्कृति से जुड़े लगभग 107 साहित्यिक लेख संग्रहित हैं।

अपने संपादकीय में, संपादक ने लोक संस्कृति, उसके साहित्य, संगीत, चित्रकला और शिल्प के महत्व को रेखांकित किया है, जो सदैव उस नींव का कार्य करती हैं जिससे उच्च सभ्यता का विकास होता है। यह अंक भारत जैसे विशाल देश की अनंत रंगीन लोक संस्कृति को समाहित करता है। जहाँ एक ओर इसमें अरुणाचल, मिजोरम आदि की सुदूर आदिवासी संस्कृति पर लेख हैं, वहीं दूसरी ओर इसमें भारत के लगभग सभी मुख्य राज्यों की लोक संस्कृति के दिलचस्प पहलुओं को दर्शाने वाले लेख भी शामिल हैं।

संपादक ने इस खंड में अवध, भोजपुरी, कन्नौज, मैथिली विदर्भ, मालवा, गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार, रवांई आदि जैसे आंचलिक लोक संस्कृति को भी पाठकों तक पहुँचाने के लिए स्थान दिया है। भारत की अनंत संस्कृतिक विविधता के दृष्टिगत, यह कहा जाता है कि समस्त विश्व की विविधता में, भारत द्वारा प्रदर्शित अनंत विविधता, को व्यक्त करने के लिए कुछ और जोड़ने की आवश्यकता होगी.. इसे पढ़ना किसी भी पाठक के लिए एक समृद्ध अनुभव होगा! मैं इस उत्कृष्ट संस्करण को श्रमपूर्वक प्रकाशित करने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं।

सुप्रसिद्ध कवि और पत्रकार सोमवारी लाल उनियाल प्रदीप ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि लोक की भावभूमि पर ही भाषा, साहित्य, संस्कृति, कला और संगीत का उद्भव होता है। लोक से अनुप्राणित होकर ही मानवीय चेतना प्रतिभानुकूल जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अग्रसर होती है। वास्तव में लोक के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। वर्तमान में हमने जो लोकतंत्र स्वीकार किया, लोक के बिना वह सार्थक ही नहीं हो सकता।

इस अवसर पर लोक संस्कृति के विषय में बोलते हुए संस्कृत के विद्वान और कवि प्रो. राम विनय सिंह ने कहा कि 'वेद' मानव जाति के ज्ञानोत्कर्ष से समाविष्ट शास्त्रीयता और पाण्डित्य का प्रशस्त मानक रूप है और 'लोक' इससे भिन्न आम जनमानस के उच्चावच भावों की अक्रम अभिव्यक्ति का स्वीकृत संसार है। यही कारण है कि कहीं वेद लोक में स्वीकृत है तो कहीं लोक ही प्रधानत: मान्य है; किंतु मानव समाज की चेतना ने इसे दो पृथक् परिपाटी के रूप में ग्रहण किया है। लोक के संस्कार, प्रथाएँ, खान-पान, पारिवारिक संबंध, वेशभूषा, आभूषण व प्रसाधन के साधन, कलाएँ, उत्सव, व्रत, औषधि ज्ञान, आर्थिक उपक्रम, धार्मिक जीवन परस्पर मानवीय भावनाएँ इत्यादि-सब मिलकर लोक और लोक संस्कृति का स्वरूप गढते हैं। निस्संदेह ये सभी तत्त्व मानवीय स्वरूप और संचेतना के साथ सर्वदा विद्यमान रहते ही रहते हैं। प्रो. सिंह ने संस्कृत की लोक दृष्टि से लेकर अधुनातन लोकभाषा और बोलियों तक की

लोकयात्रा को अत्यंत प्रभावशाली रूप में दृष्टान्त पूर्वक अभिव्यक्ति दी।

प्रारंभ में अपने वक्तव्य मे पूर्व कुलपति और विदुषी लेखिका डॉ. सुधा पांडेय ने कहा किष्नवोदित प्रवाह का लोक संस्कृति विशेषांक 'लोक संस्कृति के जीवन्त संदेश के संवाद वाहक रूप में पाठको के लिए अद्भुत लोक के वैभव के साथ परिचय देने वाला अंक है, जिसमें उत्तर से दक्षिण की लोक यात्रा का साहित्य ही नहीं लोक के रसरंग भरा जीवन चैतन्य जागृत हो उठा है। लोक भाषाओ से समृद्ध इस विशेषांक मे भारतीय सांस्कृतिक विरासत और लोक जीवन के अन्यान्य चित्र साकार हुए हैं, लोक का यह रूप मनुष्य मात्र की आत्मा का सगुण साकार रूप बन जाता हैं, जब गीत, नृत्य, जीवन के अंग बन कर लोक के अद्भुत रूप ही नहीं अपितु मनुष्य मात्र की चेतना को आनंद के रसाण र्व में मग्न कर देते हैं। वाचिक परंपरा के वैदिक मंत्रों से आहूत लोक की यह धारा चिर काल से प्राणि मात्र की रसानंद वर्षण करने वाली अमृत निस्यंदिनी धारा रही है। लोक के साहचर्य में, मनुष्य ही नहीं सारी जड़ चेतन प्रकृति आनंद करती हैं। संस्कृति वह सूत्र है जो लोक को बांध कर रखता है और साहित्य या शास्त्र उस महीन सूत्र का भास्वर रूप है। लोक का यही रूप मानव मन में बसी उस अवचेतन प्रवृत्ति का साक्षी है, जो मिथक के रूप में विभिन्न विधाओं में हर युग की साक्षी बनती है, यही मिथकीय शक्ति सामूहिक मन की मान्यताओं के रूप में हर प्रदेश के जीवन में छिपी, मिलती है, कवि और कलाकार की चेतना उसे शब्दायित करके सुर, ताल के साथ पाठकों दर्शकों के मन में ऊर्जा और आनंद का संचार करती हैं, इस भावभूमि में पंहुच कर अतीन्द्रिय आनंद की समान अनुभूति सभी भावकों को होती है, इसी अनुभूति की पृष्ठभूमि शास्त्र की जननी बन पाती है। 'नवोदित प्रवाह' का यह सुधी लेखकों के सहयोग सें भारतीय भाषाओ और लोक जीवन के महत्वपूर्ण तत्वों के साथ पाठकों कें लिए लोकार्पित हुआ है, उन्होंने संपादक मंडल को साधुवाद और बधाई दी।

पद्मश्री माधुरी बड़थ्वाल ने लोक संस्कृति में लोक संगीत के महत्व का प्रतिपादन किया और कहा कि जो संग रहे वही संगीत है। जो गीत आत्मा से निकलता है वही सच्चा लोकगीत है। हमें अपने लोक और अपनी मिट्टी से जुड़ना चाहिए।

मुख्य सूचना आयुक्त राधा रतूड़ी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में लोक संस्कृति और लोक जीवन के विविध पक्षों पर प्रकाश डाला। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि नवोदित प्रवाह का यह संकलन लोक संस्कृति पर केन्द्रित है। यह अंक उत्तराखण्ड के अलावा देश के विविध क्षेत्र समाज की आत्मा को गहराई से प्रदर्शित करने में पूरी तरह से सक्षम है। भारत देश के अलग-अलग प्रान्तों की सांस्कृतिक विविधताओं को बहुत ही कुशलता से त्रिवेदी जी ने इस अंक में प्रस्तुत कर संजोया है।

कार्यक्रम के प्रारंभ में नवोदित प्रवाह के संपादक रजनीश त्रिवेदी 'आलोक' ने स्वागत संबोधन दिया। कार्यक्रम का कुशल संचालन कवयित्री भारती मिश्रा ने किया। कार्यक्रम के समापन से पूर्व उपस्थित अतिथियों व लोगों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन केंद्र के कार्यक्रम अधिकारी चंद्रशेखर तिवारी ने दिया।

इस अवसर पर पूर्व मुख्य सचिव उत्तराखण्ड नृप सिंह नपलच्याल, सोमवारी लाल उनियाल प्रदीप, कृपा राम नौटियाल, डॉ. पंकज नैथानी, डॉ. दाता राम पुरोहित, डी. के. कांडपाल, तापस चक्रवर्ती, जयप्रकाश खंकरियाल, सत्यानंद बडोनी, मंजू काला,सोमेश्वर पाण्डेय, हरि चंद निमेष, सचिन चौहान, श्रद्धा मिश्रा, डॉ. क्षमा कौशिक, कविता बिष्ट, डॉ. लालिमा वर्मा, डॉ. आर.पी. भारद्व ाज भगवान प्रसाद घिल्डियाल, डॉ. सुदेश ब्याला, डॉ. बैजनाथ, मधुलिका श्रीवास्तव, सुनील त्रिवेदी, सतीश बंसल, दर्द गढ़वाली केंद्र के पुस्तकालयाध्यक्ष डॉ. डी.के. पांडे, सुंदर सिंह बिष्ट, जगदीश सिंह महर, डॉ. लालता प्रसाद, राकेश कुमार सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्ध लोग, पाठक व रचनाकार उपस्थित रहे।

टिहरी के ज्वलंत मुद्दों पर मुख्यमंत्री की चुप्पी निराशाजनक: राकेश राणा

जिला कांग्रेस कमेटी टिहरी गढ़वाल के पूर्व अध्यक्ष राकेश राणा ने कहा कि वर्तमान समय में जनपद के ज्वलंत मुद्दों पर प्रदेश के मुख्यमंत्री का चुप रहना निराशाजनक हे।

प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कोटी कॉलोनी में आयोजित टिहरी लेक फेस्टिवल में भाग लेने पहुँचे। टिहरी की जनता ने उनका खूब स्वागत तो किया, लेकिन उनके संबोधन में जनपद के ज्वलंत मुद्दों पर कोई स्पष्ट चर्चा या ठोस आश्वासन न होने से क्षेत्र की जनता में गहरी निराशा देखने को मिली। टिहरी जनपद आज कई गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। टिहरी मेडिकल कॉलेज की स्थापना का मुद्दा वर्षों से लंबित है, जंगली जानवरों के बढ़ते आतंक से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का जीवन असुरक्षित होता जा रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ पर्याप्त नहीं हैं, गर्भवती महिलाएं अस्पताल में आने से पहले दम तोड़ती जा रही है, और युवाओं के सामने रोजगार के अवसरों की भारी कमी है। इन परिस्थितियों के कारण क्षेत्र से लगातार पलायन बढ़ता जा रहा है, जो टिहरी के भविष्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इसके साथ ही टिहरी बांध से प्रभावित और विस्थापित हजारों परिवार आज भी अपने अधिकारों और मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हनुमंता राव समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रभावितों और विस्थापितों को बिजली और पानी रियायती दरों पर उपलब्ध कराने का मुद्दा भी लंबे समय से लंबित है, लेकिन इस महत्वपूर्ण विषय पर भी मुख्यमंत्री के संबोधन में कोई स्पष्टता नहीं दिखी। जबकि पूर्व मंत्री प्रकाश पंत के द्वारा इसकी घोषणा की गई।

कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश राणा ने कहा कि क्षेत्र के विकास और लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए केवल उत्सव और मंचीय भाषण पर्याप्त नहीं हैं। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार इन ज्वलंत मुद्दों पर गंभीरता से विचार करे और एक ठोस, समयबद्ध तथा प्रभावी कार्ययोजना सामने लाए।

टिहरी की जनता ने वर्तमान सरकार को एक तरफा बहुमत देने के बाद अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर ठोस विकास और न्याय चाहती है।

टिहरी फेस्टिवल ने साबित की उत्तराखण्ड की क्षमताः राज्यपाल

अपने संस्मरणों से खींची महिला सशक्तिकरण की तस्वीर

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से.नि.) ने रविवार को टिहरी गढ़वाल में आयोजित *'द टिहरी लेक फेस्टिवल'* कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि 'द टिहरी लेक फेस्टिवल' के जरिये पर्यावरण, बारामासी पर्यटन, संस्कृति और साहसिक खेल से जुड़े बड़े संदेश देश-दुनिया तक पहुंचे हैं। इसने न सिर्फ टिहरी, बल्कि पूरे उत्तराखण्ड की क्षमता को साबित किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में उत्तराखण्ड अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

राज्यपाल ने *'द टिहरी लेक फेस्टिवल'* कार्यक्रम के आयोजकों की सराहना करते हुए कहा कि चार दिन में 15 से अधिक प्रतियोगिताएं और उनमें साढ़े तीन हजार प्रतिभागियों की उपस्थिति उत्साहित करने वाली है। पहली बार आयोजन का दायरा बढ़ने और इसमें विभिन्न विषयों के समावेश को उन्होंने खास तौर पर रेखांकित किया।

चार संस्मरणों से महिला शक्ति का बखान

अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के आलोक में राज्यपाल ने अपने संबोधन के एक बड़े हिस्से को महिलाओं पर केंद्रित किया। उन्होंने कहा-पहाड़ की बेटियों के लक्ष्य बहुत ऊंचे हैं। वह बेहद मजबूत और दृढ़ इच्छा शक्ति वाली हैं। उन्होंने चार संस्मरणों के जरिये दिलचस्प ढंग से महिला शक्ति का बखान किया।

संस्मरण-01

राज्यपाल ने पहला संस्मरण एनसीसी कैडेट से संबंधित साझा किया। उन्होंने बताया-देहरादून के एक कार्यक्रम में नौवीं कक्षा की एनसीसी कैडेट से जब उन्होंने उसका लक्ष्य पूछा, तो उसने कहा-वह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनेगी।

संस्मरण-02

टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एआई आधारित कॉम्पिटीशन की प्रतिभागी बेटी से मुलाकात का राज्यपाल ने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस बेटी ने मुझसे कहा-आई लव टेक्नोलॉजी। साफ संकेत है-हमारी बेटियां तकनीक की अहमियत समझ रही हैं।

संस्मरण-03

राज्यपाल ने अपने पहले विजिट का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वह अपने पहले विजिट में एक स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से मिले थे, जो नौ तरह का पहाड़ी लूण बनाती हैं। यह लूण न्यूयॉर्क और लंदन में भी बिकता है।

संस्मरण-04

राज्यपाल ने अल्मोड़ा की मशरूम उत्पादक महिला की भी चर्चा की और बताया कि वह 25 हजार रूपये महीना कमाती थी। मैंने छह महीने में एक लाख कमाने की अपेक्षा की, जो उसने पूरी कर दी। अब उससे एक करोड़ सालाना कमाई की अपेक्षा है।

जल, जंगल, जमीन, टिहरी सारे विषयों को छुआ

राज्यपाल ने जल, जंगल, जमीन से लेकर टिहरी के इतिहास और यहां से जुड़ी तमाम बातों को अपने भाषण का हिस्सा बनाया। उन्होंने पहाड़ के खाद्य पदार्थों, व्यंजनों, श्री अन्न को भी अपने भाषण की विषय वस्तु बनाया।

हिमालयन ओ टू और छुई बाथ की खास चर्चा

राज्यपाल ने आयोजन के साथ हिमालयन ओ टू जोड़े जाने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण का इससे बड़ा कोई संदेश नहीं हो सकता। छुई बाथ जैसे कार्यक्रम की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें हुई चर्चाओं को किताब रूप में संकलित किए जाने की जरूरत है। उन्होंने हिमालयी सरोकारों के लिए विधायक किशोर उपाध्याय की भी तारीफ की।

पीएम की सोच को आगे बढ़ा रहा उत्तराखण्ड

राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संदेश दिया है कि उत्तराखण्ड में सिर्फ चारधाम से संबंधित यात्रा ही नहीं है, बल्कि बारह महीने की संभावनाएं हैं। इस पर अमल करते हुए उत्तराखण्ड शीतकालीन, ग्रामीण, सांस्कृतिक आदि पर्यटन को आगे बढ़ाने की कोशिशों में जुटा है।

विजेताओं को पुरस्कार बांटे, नाट्य प्रस्तुति सराही

राज्यपाल ने पेंटिंग, मास्टर शेफ, ग्रुप फैशन शो, मिस्टर एवं मिसेज टिहरी आदि प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से उन्हें पहाड़ी वाद्य यंत्र रणसिंगा से संबंधित स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सुर गंगा संगीत कला मंच की ओर से नाट्य प्रस्तुति दी गई, जिसकी राज्यपाल ने सराहना की।

हेलीपैड पर हुआ राज्यपाल का जोरदार स्वागत

इससे पहले, यहां पहुंचने पर हेलीपैड पर राज्यपाल का विधायक किशोर उपाध्याय, डीएम नितिका खंडेलवाल, एसएसपी आयुष अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष इशिता सजवाण, भाजपा जिलाध्यक्ष उदय रावत सहित अन्य जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने स्वागत किया।

कार्यक्रम में दायित्वधारी राज्य मंत्री विनोद उनियाल, गीता रावत, सचिव राज्यपाल रविनाथ रामन, नगर पालिका परिषद नई टिहरी के अध्यक्ष मोहन सिंह रावत व चंबा की अध्यक्ष शोभनी धनोला आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन राकेश बधानी ने किया।

जानिए कैसा होगा आपका यह सप्ताह

पं. दीपक प्रसाद, शास्त्री (मो. 9557730042)
(ज्योतिष, कर्मकाण्ड, धर्मिक अनुष्ठान आदि)

मेष- किसी उलझे हुए मामले का समाधान मिलने से राहत रहेगी। भावुकता से ज्यादा बुद्धि और कार्यकुशलता का उपयोग करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कुछ समय व्यावहारिक और प्रभावशाली लोगों के साथ बिताने से आपके स्वभाव और सोच में सकारात्मक बदलाव आएगा। कारोबार में कुछ मंदी का असर दिख सकता है।

वृषभ- आर्थिक दृष्टि से समय अनुकूल है। उधार दिया हुआ या अटका पैसा मिलने की अच्छी संभावना है। किसी भी फैसले को दिल की जगह दिमाग से लेना जरूरी रहेगा। इससे आप सही और गलत की बेहतर पहचान कर पाएंगे। धार्मिक और सामाजिक कामों में आपका विशेष योगदान रहेगा, जिससे सम्मान भी बढेगा। रुपये-पैसे के लेनदेन में बहुत सावधानी रखें।

मिथुन- किसी खास व्यक्ति की सलाह से लाभ मिल सकता है, इसलिए अच्छे लोगों की बात ध्यान से सुनें। अगर प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त से जुडी कोई योजना चल रही है, तो उसमें गति आ सकती है। आर्थिक स्थिति बेहतर होने से दिनभर की थकान भी कम लगेगी और मन हल्का रहेगा। आपके विचारों में संकीर्णता या जिद की वजह से कुछ लोग असहज हो सकते हैं।

कर्क- समय के अनुसार काम पूरे होते जाएंगे, जिससे खुशी और संतोष मिलेगा। अगर कोई सरकारी मामला अटका हुआ है, तो उसे सुलझाना अपेक्षाकृत आसान रहेगा। ससुराल पक्ष से कोई खुशखबरी मिल सकती है। परिवार और वित्त से जुडे फैसले भी आपके पक्ष में रहेंगे। सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ से मानसिक सुकून मिलेगा। मेडिटेशन आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

सिंह- बच्चों से जुडी किसी समस्या का समाधान मिलने से मन में संतोष रहेगा। इससे आप बाकी गतिविधियों पर भी अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। ग्रह स्थिति काफी संतोषजनक है। आपकी समझ और बुद्धिमानी से परिवार से जुडा लिया गया कोई फैसला बहुत सकारात्मक साबित होगा। व्यवसाय में फायदेमंद स्थितियां बनी हुई हैं।

कन्या- सोचे हुए काम समय पर पूरे हो जाएंगे। दिन व्यस्त रहेगा, लेकिन मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। नजदीकी संबंधियों के साथ गेट-टुगेदर जैसा कार्यक्रम बन सकता है। आपसी मेलजोल से खुशी और हल्कापन दोनों मिलेगा। आर्थिक रूप से कुछ उलझनें आ सकती हैं, हालांकि आप उन्हें समय रहते सुलझा लेंगे।

तुला- नजदीकी संबंधियों के साथ मिलकर कुछ खास योजनाओं पर चर्चा होगी। रुकी हुई पेमेंट मिलने से राहत मिलेगी। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में भी रुझान बढेगा। परिवार के साथ किसी मनोरंजक यात्रा की योजना बन सकती है। युवा वर्ग बेकार की गतिविधियों में समय खराब कर सकता है, जिससे नुकसान होने की आशंका है।

वृश्चिक- आय के स्रोत बढेंगे। अपनी कार्यशैली और व्यक्तित्व को बेहतर बनाने के लिए किए गए प्रयास सफल रहेंगे। प्रयासरत युवाओं को करियर से जुडी किसी समस्या का समाधान मिलने से राहत और सुकून मिलेगा। आत्मविश्वास भी बढेगा। अपनी कार्यप्रणाली को गोपनीय रखना जरूरी है। आसपास हो रही गतिविधियों को नजरअंदाज न करें।

धनु- किसी खास योजना को लागू करने से पहले अनुभवी लोगों की राय लेना आपकी मुश्किलों को आसान करेगा। समाज में आपका मान-सम्मान और प्रभाव बना रहेगा। सूझबूझ से आप किसी भी काम को पूरा करने में सक्षम रहेंगे। आपकी रणनीति और आत्मविश्वास दोनों असरदार रहेंगे। बीती हुई कोई नकारात्मक बात वर्तमान पर हावी होने से संबंधों में खटास ला सकती है।

मकर- इस समय वित्तीय मामलों पर खास ध्यान दें। आपकी कोई योजना साकार हो सकती है। रुके हुए कामों में प्रगति आएगी और आप अपनी योग्यता व प्रतिभा के बल पर उन्हें पूरा करने में सफल रहेंगे। मनोरंजक योजनाएं भी बनेंगी, जिससे मन हल्का रहेगा। रिश्तों में शक जैसी स्थिति को जगह न दें। बेहतर होगा कि छोटी-मोटी नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करें।

कुंभ- दिन की शुरुआत में ही अपने जरूरी कामों की योजना बना लें, दोपहर बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में ज्यादा अनुकूल रहेंगी। फाइनेंस से जुडी गतिविधियां बेहतर होंगी और मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। राजनीति से जुडे लोगों को कोई खास उपलब्धि मिलने की उम्मीद है। अपने निजी कामों पर ही ध्यान दें। दूसरों के मामलों में दखल देने से केवल समय खराब होगा।

मीन- आपकी आर्थिक योजना से जुडा कोई लक्ष्य पूरा होने के करीब है। इसलिए मेहनत में बिल्कुल कमी न आने दें। किसी संबंधी के साथ महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होगी और उसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आएंगे। महिलाएं व्यस्तता के बावजूद अपने निजी कामों के लिए समय निकाल लेंगी। भाई-बहनों के साथ रिश्तों में मिठास बनाए रखने में आपका योगदान जरूरी है।

'धुरंधर: द रिवेंज' में यामी गौतम के किरदार से उठा पर्दा क्या रणवीर सिंह पर भारी पड़ेंगी हसीना?

ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' की सफलता के बाद फैंस इसके सेकंड पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 19 मार्च को रिलीज हो रही स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' के 18 मार्च वाले 'पेड प्रीव्यू' के बाद अब मूवी की एडवांस बुकिंग भी ओपन हो गई है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में जहां एक तरफ रणवीर सिंह का 'जसकीरत सिंह रंगी' से 'हमजा अली मजारी' बनने तक का सफर दिखाया जाएगा, तो वहीं सेकंड पार्ट में यामी गौतम की भी धमाकेदार एंट्री हो रही है। काफी समय से फैंस के मन में यह सवाल उठ रहा था कि 'धुरंधर 2' में यामी गौतम का किरदार क्या होगा?

19 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देगी 'धुरंधर: द रिवेंज'

'धुरंधर' के बाद तुरंत 'धुरंधर: द रिवेंज' को रिलीज करने की मेकर्स की रणनीति काफी असरदार साबित हुई है। फैंस को लंबा इंतजार न करवाते हुए सिर्फ 2 महीने के भीतर ही इसके दूसरे पार्ट को रिलीज करने के निर्णय से फिल्म का बज लगातार बना रहा। इसी का नतीजा है कि वर्ल्डवाइड एडवांस बुकिंग में मूवी ने 60 करोड़ रुपये के आसपास की शानदार कमाई कर ली है। 'धुरंधर 2' अगले हफ्ते गुरुवार, 19 मार्च को ईद के खास अवसर पर रिलीज हो रही है। आदित्य धर की इस स्पाई थ्रिलर फिल्म में रणवीर सिंह और यामी गौतम के अलावा सारा अर्जुन, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और आर. माधवन जैसे दिग्गज सितारे मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगे।

'धुरंधर 2' में ऐसा होगा यामी गौतम का किरदार?

एक रिपोर्ट के मुताबिक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक ट्वीट काफी वायरल हो रहा है। इस ट्वीट में दावा किया जा रहा है कि यामी गौतम 'धुरंधर: द रिवेंज' में बहुत ही इंटेंस किरदार अदा करने वाली हैं। वह फिल्म में एक एजेंट बनकर 'हॉस्पिटल के एक सीक्वेंस' में जबरदस्त एक्शन मोड में नजर आएंगी। हालांकि, मेकर्स की तरफ से उनके किरदार को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी शेयर नहीं की गई है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर फैंस इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर रणवीर सिंह का किरदार 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' वाले 'जसकीरत सिंह रंगी' का है, तो क्या यामी गौतम भी फिल्म में अपनी रॉ एजेंट 'पल्लवी शर्मा' का किरदार ही दोहराएंगी या फिर वे किसी नए अवतार में दिखेंगी? अगर वह अपने पुराने एजेंट वाले किरदार को ही आगे बढ़ाती हैं, तो एक्शन सीक्वेंस में वे रणवीर सिंह को कड़ी टक्कर देती नजर आ सकती हैं।

राम गोपाल वर्मा ने की आदित्य धर की तारीफ

रेडिफ को दिए एक इंटरव्यू में आरजीवी ने आदित्य की शिल्प कौशल और फिल्म टेक्निक्स पर उनकी पकड़ की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके काम ने पर्दे पर कहानियों को बताने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है।

> ***राम गोपाल वर्मा ने कहा-*** **'आपको समझना होगा कि आदित्य धर ने मूवी बिजनेस के लिए क्या किया है। उन्होंने ऑनलाइन स्टोरीटेलिंग का पूरा व्याकरण ही बदलकर रख दिया है। हमारी फिल्में अब वैसी नहीं रहेंगी और ये मैं सिर्फ हिंदी की नहीं सभी भाषाओं की बात कर रहा हूं। इसका मतलब है भारी बजटीय देनदारी। इसलिए, जाहिर है, वे उनसे नफरत करते हैं। उन्होंने सभी को अपने कॉम्फर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया है और इसमें बहुत पैसा खर्च होता है।'**

यामी गौतम की हक मूवी की तारीफ की

निर्देशक ने यामी गौतम की फिल्म 'हक' के बारे में भी बात की। ये एक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म थी जिसमें यामी के साथ इमरान हाशमी लीड रोल में नजर आए थे। सुपन वर्मा इसके निर्देशक हैं। यह फिल्म मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से प्रेरित है, जिसमें मुस्लिम परिवारों में वैवाहिक अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई थी। राम गोपाल ने कहा कि आदित्य धर और यामी गौतम को बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री उनके लड़खड़ाने और गिरने का इंतजार कर रही है।

EXPERIENCE HELI TOUR WITH

Himgiri
Aviation & Tourism
SINCE 2018

3N/4D TOUR

A Unit of
दिव्य हिमगिरि

केदार-बद्री यात्रा

BY HELICOPTOR

OPENING DATES

KEDARNATH
22 April, 2026

BADRINATH
23 April, 2026

ADVANCE BOOKING STARTS BOOK NOW

Contact for Reservation 8433456398, 9410353164

Email: himgiritourism@gmail.com
6 Municipal Road, Opp. Oxford School of Excellence, Dalanwala, Dehradun-248001 (UK)

R.N.I.: UTTHIN/2010/41629 | Postal Regd. UA/DO/DDN/01/2025-2027